नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 297, नई दिल्ली, शनिवार 27 दिसम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में वही व्यक्ति दुखी है जो ख़ाली है काम मैं व्यस्त रहो और मस्त रहो।

03 हनुमान जी के 5 सगे भाई

06 रीसाइक्लिंग हमारे प्लास्टिक संकट को हल नहीं कर सकती

08 भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर चेतावनी दी, ...

देश के प्राइवेट ड्राइवर: सड़क हादसा, बीमा और न्याय से दूर परिवार

लेखक: संजय कुमार बाठला

(लेखक परिवहन नीतियों और श्रमिक अधिकारों पर सक्रिय सामाजिक विश्लेषक हैं।)

हादसे के बाद बेसहारा होता ड्राइवर परिवार जब किसी प्राइवेट ड्राइवर की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट रोटी, इलाज और बच्चों की पढ़ाई का खड़ा हो जाता है। यह वे परिवार होते हैं जो पहले ही कम आय, असंगठित रोजगार और बिना सामाजिक सुरक्षा के किसी तरह गुजारा कर रहे होते हैं। पत्नी, छोटे बच्चे, बुजुर्ग मां–बाप और कई बार अविवाहित बहन–भाई तक अचानक सहारे से वंचित हो जाते हैं और घर चलाने वाला एकमात्र कमाने वाला सदस्य हमेशा के लिए चला जाता है।

ऐसी स्थिति में कानून और व्यवस्था का पहला कर्तव्य होता है कि वह पीड़ित परिवार को त्वरित, सरल और पर्याप्त आर्थिक सहायता तथा न्याय उपलब्ध कराए, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी इसके उलट दिखाई देती है।

मोटर व्हीकल कानून: कागज़ पर सुरक्षा, ज़मीन पर मुश्किल भारत में मोटर वाहन से होने वाले हादसों के मामलों में मुआवज़े का ढांचा मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) से तय होता है।

धारा 140: "नो फॉल्ट लायबिलिटी" – यदि किसी व्यक्ति की मौत या स्थायी विकलांगता मोटर वाहन दुर्घटना से होती है तो वाहन मालिक को बिना गलती साबित हुए भी एक निश्चित अंतरिम मुआवज़ा देना होता है।

धारा 163A: विशेष प्रावधान – संरचित फ़ॉर्मूला के आधार पर मुआवज़ा, जिसमें मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति दी जानी है और इसके लिए भी गलती साबित करना अनिवार्य नहीं है।

धारा 147: यह अनिवार्य करती है कि हर मोटर वाहन की पॉलिसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को होने वाले नुकसान/मौत के लिए बीमा कवर दे।

कानून की मंशा साफ है कि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित या उसके परिजन को लंबी कानूनी लड़ाई के बिना भी मूलभूत मुआवज़ा मिले, लेकिन व्यवहार में बीमा कंपनियां, कागज़ी आपत्तियों, तकनीकी खामियों और लंबी प्रक्रियाओं के ज़रिए क्लेम को रोकती या टालती रहती हैं।

ड्राइवर का बीमा: नियम तो हैं, पर ड्राइवर अब भी असुरक्षित आज भारत में हर वाहन मालिक के लिए "कम्पल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर" (Compulsory Personal Accident Cover) रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के निर्देशों के अनुसार, 2018 से मोटर बीमा पॉलिसी में ओनर-ड्राइवर के लिए अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर जोड़ना आवश्यक किया गया, जिसकी बीमित राशि बाद के संशोधनों में अधिकतम 15 लाख रुपये तक निर्धारित की गई।

2019 से यह भी व्यवस्था बनी कि यह कवर स्टैंड-अलोन पॉलिसी के रूप में भी खरीदा जा सकता है; यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से 15 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है, तो हर वाहन पर अलग–अलग पी.ए. कवर लेना ज़रूरी नहीं।

कागज़ पर यह व्यवस्था ड्राइवर की सुरक्षा के लिए बनाई गई, परंतु व्यवहार में अधिकतर प्राइवेट ड्राइवरों को न तो अपनी पॉलिसी की सही जानकारी होती है, न क्लेम की प्रक्रिया की। बहुत से मामलों में वाहन मालिक बीमा तो करा देते हैं, लेकिन प्रीमियम और पॉलिसी दस्तावेज़ तक ड्राइवर की पहुंच नहीं होती, जिससे दुर्घटना के बाद ड्राइवर परिवार क्लेम पाने के अधिकार से वंचित रह जाता है।

क्लेम की राह: पुलिस, कोर्ट और लंबी कानूनी लड़ाई दुर्घटना के बाद ड्राइवर के परिवार को राहत पाने के लिए सबसे पहले एफआईआर, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) में दावे की प्रक्रिया से

गुजरना पड़ता है।

अधिकतर गरीब परिवार कानूनी भाषा, दस्तावेज़ी जरूरतों और वकील की फीस से घबराकर शुरुआत ही नहीं कर पाते।जो 10–15 प्रतिशत परिवार हिम्मत कर के केस दर्ज करवाते हैं, वे भी कई बार सालों तक इंसाफ का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि इस दौरान बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया और रोज़मर्रा का खर्च चलाना लगभग असंभव हो जाता है।

महिला विधवाओं के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाती है – उन्हें एक ओर बच्चों का पालन–पोषण करना होता है, दूसरी ओर पुलिस थाने, बीमा दफ्तर और अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

ऐसे में न्याय–प्रणाली की जटिलता खुद एक प्रकार का दमन बन जाती है, जो पहले से पीड़ित वर्ग को और कमजोर करती है।

प्रधानमंत्री बीमा योजनाएँ: ड्राइवर वर्ग को जोड़ने की ज़रूरत केंद्र सरकार द्वारा शुरू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – PMSBY) कम प्रीमियम वाली एक महत्वपूर्ण दुर्घटना बीमा योजना है, लेकिन इसका लाभ संगठित रूप से ड्राइवर वर्ग तक अभी भी नहीं पहुंच पाया है।

*योजना के तहत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता कवर और 1 लाख रुपये तक का आंशिक स्थायी विकलांगता कवर उपलब्ध है।

*18 से 70 वर्ष आयु के व्यक्ति अपने बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन असंगठित ड्राइवरों की बड़ी संख्या या तो बैंकिंग चैनल से दूर है या योजना की जानकारी से।

* यदि सभी कमर्शियल/ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial Driving Licences) को किसी प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के साथ स्वतः लिंक कर दिया जाए, तो लाखों ड्राइवरों के परिवारों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित की जा सकती है।

नीति सुधार की ज़रूरत: लाइसेंस के साथ अनिवार्य ड्राइवर बीमा आज समय की मांग है कि मोटर व्हीकल एक्ट और संबंधित नियमों में निम्नलिखित सुधार किए जाएँ:

*** ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अनिवार्य दुर्घटना बीमा** जिस समय नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो या पुराना नवीनीकृत हो, उसी समय न्यूनतम 15 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर ड्राइवर के नाम से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

*** लाइसेंस पर बीमा पॉलिसी नंबर, कंपनी का नाम और बीमित राशि स्पष्ट रूप से अंकित हो**, ताकि सड़क हादसे की स्थिति में पुलिस, अस्पताल और न्यायालय तुरंत इसकी पुष्टि कर सकें।

*** प्रीमियम वसूली का सरल मॉडल** बीमा प्रीमियम सीधे लाइसेंस फीस के साथ जोड़कर लिया जा सकता है; जैसा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये सालाना जैसी कम प्रीमियम संरचना सफल रही है।

*** राज्य परिवहन विभाग और बीमा कंपनियों के बीच MoU के ज़रिए समूह बीमा (Group Insurance) मॉडल अपनाया जाए**, जिससे प्रीमियम और भी कम हो सके।

*** नो–फॉल्ट त्वरित मुआवज़ा तंत्र** धारा 140 और 163A के तहत निर्धारित मुआवज़े को ड्राइवर वर्ग के लिए न्यूनतम राशि के रूप में "ऑटो–क्रेडिट" मॉडल में लागू किया जाए, ताकि दुर्घटना के 30–60 दिन के भीतर परिवार के खाते में मूल राहत राशि पहुंच जाए।

*** MACT के समक्ष लंबी सुनवाई आगे चलकर अंतिम मुआवज़े की राशि तय करे,** लेकिन प्रारंभिक राहत में देरी न हो।

डुप्लीकेट/बिना लाइसेंस वाहन संचालन पर सख्त नियंत्रण

* कमर्शियल वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस और सक्रिय बीमा लिंक होना अनिवार्य किया जाए; बिना लाइसेंस या फर्जी लाइसेंस पर पकड़े जाने पर सिर्फ चालान नहीं, वाहन के परमिट पर भी कार्रवाई हो।

* लाइसेंस–बीमा लिंक से फर्जी लाइसेंस रैकेट और करप्शन को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि बिना वैध बीमा पॉलिसी के लाइसेंस डेटा अधूरा और आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

ड्राइवर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और नीतिगत न्याय सिर्फ बीमा ही नहीं, प्राइवेट ड्राइवरों के लिए सम्मानजनक न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत स्पष्ट श्रमिक दर्जा और पेंशन/ईएसआई जैसी सुविधाएँ भी जरूरी हैं।

परिवहन/टूरिस्ट/कैब सेक्टर में काम कर रहे ड्राइवरों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन, ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश और अधिकतम ड्यूटी घंटे के मानक अलग से तय किए जाने चाहिए।

राज्य और केंद्र, दोनों स्तर पर ड्राइवर यूनियन को नीति–निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड या समर्पित कल्याण कोष की स्थापना की जा सकती है, जिसमें जुर्माने, परमिट शुल्क और बीमा कंपनियों के CSR का एक हिस्सा जोड़ा जाए।

देश की अर्थव्यवस्था, माल–ढुलाई और आम जनता की दैनिक आवाजाही में ड्राइवरों का योगदान किसी भी तरह कम नहीं है, परंतु नीतिगत प्राथमिकताएँ अभी भी उन्हें "जोखिम उठाने वाला, पर अधिकारों से वंचित" वर्ग बनाए हुए हैं।

जनहित में अपील आप जैसे निर्णय – कारी नेतृत्व से अपेक्षा है कि:

* मोटर वाहन अधिनियम और बीमा नियमों में संशोधन कर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अनिवार्य, पर्याप्त और पारदर्शी दुर्घटना बीमा जोड़ा जाए।

* सभी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या इसी प्रकार की किसी राष्ट्रीय दुर्घटना बीमा योजना से स्वतः लिंक किया जाए।

* बीमा क्लेम प्रक्रिया को सरल, समय–बद्ध और ऑनलाइन ट्रैकिंग–युक्त बनाया जाए, ताकि ड्राइवर परिवार को न्याय के लिए सालों–साल कोर्ट–कचहरी के चक्कर न लगाने पड़ें।

यह मांग किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देशभर के उन लाखों ड्राइवर परिवारों की है जिन पर भारत की सड़कें, अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों की रोज़मर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। ड्राइवर को अपराधी नहीं, देश की रीढ़ की हड्डी समझकर नीतियाँ बनाना ही सच्चा जनकल्याण होगा।

दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी संपत्तियों पर 'नवाचार' के नाम पर कब्जे की नई शुरुआत

संजय कुमार बाठला

सारांश विषय: दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी की संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया और नई मुख्यालय परियोजना

प्रेषक: संजय कुमार बाठला

दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की संपत्तियों पर पुनर्गठन और वाणिज्यिक विकास के नाम पर नियंत्रण प्रक्रिया शुरू की है। इस कड़ी में डीटीसी और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत आई.पी. बस डिपो परिसर में लगभग 207 करोड़ रुपये की लागत से 12 मंजिला नया डीटीसी मुख्यालय बनाया जाएगा। परियोजना में 200 बसों और 200 से अधिक कारों के लिए पार्किंग, सौर संयंत्र, वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसे ढाई वर्षों में पूरा करने की योजना है। जानकारों और कर्मचारियों का कहना है कि यह कदम धीरे-धीरे डीटीसी को दिल्ली विद्युत बोर्ड की तरह समाप्त करने की दिशा में ले जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली की सार्वजनिक बस सेवा, जो दशकों से राजधानी की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ रही है, इतिहास बन सकती है। यह मुद्दा दिल्ली के नागरिकों और परिवहन से जुड़े सभी पक्षों के हित में गंभीर विमर्श का विषय है।

दिल्ली: राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के ऐतिहासिक प्रतीक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की संपत्तियों पर अब दिल्ली सरकार द्वारा पुनर्संरचना के नाम पर नियंत्रण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

विशेषज्ञों और कर्मचारियों का मानना है कि यह कदम उसी दिशा में है, जिस तरह अतीत में दिल्ली विद्युत बोर्ड को भंग कर दिया गया था। यदि यही रफ्तार जारी रही तो डीटीसी का अस्तित्व भी जल्द इतिहास बन सकता है।

बीते मंगलवार को डीटीसी और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के बीच आई.पी. बस डिपो परिसर में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत लगभग 207 करोड़ रुपये की लागत से एक नया डीटीसी मुख्यालय निर्मित किया जाएगा, जो 26,015 वर्ग मीटर भूमि पर फैला होगा।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह इस हस्ताक्षर समारोह के साक्षी रहे। उनके अनुसार, यह परियोजना दिल्ली के बढ़ते परिवहन नेटवर्क को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए परिसर में 200 बसों व 200 से अधिक कारों के लिए पार्किंग, सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संचयन, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी।परियोजना लगभग ढाई वर्षों में पूरी की जानी है, जिसका निर्माण कार्य डीएसआईआईडीसी करेगा।

12 मंजिला इस इमारत में डीटीसी के विभिन्न विभागों के लिए कार्यालयीय खंडों के साथ-साथ वाणिज्यिक उपयोग हेतु भी जगह रखी जाएगी, ताकि भविष्य में निगम को राजस्व प्राप्त होता रहे।

हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस समझौते के पीछे सरकार की मंशा केवल नये मुख्यालय तक सीमित नहीं बल्कि धीरे-धीरे डीटीसी की परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक उपयोग में लाने की है।

कर्मचारियों के बीच यह आशंका गहराती जा रही है कि जिस प्रकार दिल्ली विद्युत बोर्ड निजीकरण की भेंट चढ़ा, उसी तरह डीटीसी भी प्रशासनिक अस्तित्व खो सकता है।

यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली लाल बसें — जो दशकों से राजधानी के सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ हैं — इतिहास का हिस्सा बन सकती हैं।

केंद्रीय इस्पात व भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी से मिले उफ्तत्सा (राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव

नई दिल्ली/राउरकेला।

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा – ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी से नई दिल्ली में उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात औपचारिक रूप से इस्पात उद्योग से जुड़े जमीनी मुद्दों, परिवहन तंत्र, ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं और नीति सुधारों पर केंद्रित एक गंभीर व सार्थक संवाद में परिवर्तित हुई।

भेंट के दौरान डॉ. यादव ने देश के प्रमुख इस्पात संयंत्रों—विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों—से जुड़े परिवहन तंत्र की वास्तविक स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले ट्रक मालिक, ट्रांसपोर्टर और संलग्न व्यवसाई आज अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और अंततः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

डॉ. यादव ने इस्पात संयंत्रों में माल ढुलाई से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं तथा स्थानीय ट्रांसपोर्टरों की उपेक्षा जैसे मुद्दों को तथ्यों के साथ रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि परिवहन व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और ट्रक मालिकों के अनुकूल नहीं बनाया गया, तो "मेक इन इंडिया" ₹ लोकल फॉर वोकल ₹ और ₹औद्योगिक विकास₹ की गति प्रभावित हो सकती है।

केंद्रीय मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी ने डॉ. यादव की बातों को गंभीरता से सुना। माननीय मंत्री ने पुनः नए वर्ष पर मुलाक़ात का समय दिया व कहा कि भविष्य में इस्पात संयंत्रों में लॉजिस्टिक्स सुधार, डिजिटल प्रक्रियाओं को सरल बनाने, स्थानीय ट्रांसपोर्टरों की भागीदारी बढ़ाने और भुगतान प्रणाली को समयबद्ध करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी।

भेंट के पश्चात डॉ. राजकुमार यादव ने कहा कि यह संवाद केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि देशभर के लाखों ट्रक चालकों, ट्रांसपोर्टरों और मोटर मालिकों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप से इस्पात उद्योग से जुड़ा परिवहन क्षेत्र नई मजबूती के साथ आगे आएगी।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार

दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री डी.के. उपाध्याय का डिजिटल उगाही पर वक्तव्य

हाल ही में डिजिटल उगाही पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन समारोह में माननीय मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने महत्वपूर्ण विचार साझा किए:

"डिजिटल उगाही हर इंटरनेट उपयोगकर्ता पर एक छाया है।"

यह कथन इस खतरे की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। चाहे छात्र हो, गृहिणी, पेशेवर या सेवानिवृत्त व्यक्ति—कोई भी सुरक्षित नहीं है। इंटरनेट ने जहाँ लोगों को सशक्त बनाया है, वहीं यह भय और धोखे का माध्यम भी बन गया है। अपराधी डिजिटल कमजोरियों का फायदा उठाकर पीड़ितों को डराते, ब्लैकमेल करते और मानसिक रूप से जकड़ लेते हैं।

"ये अपराध केवल पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि वकीलों और न्यायाधीशों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि अपराधी कानूनी प्रतीकों और प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर पीड़ितों को धोखा देते हैं।"

उन्होंने बताया कि अब ठग न्यायिक अधिकारियों का रूप धारण करते हैं, नकली गिरफ्तारी वारंट बनाते हैं और कानून की भाषा का इस्तेमाल कर भय पैदा करते हैं। अदालत की मुहर, एफआईआर का प्रारूप और आईपीसी की धाराओं का दुरुपयोग कर अपराधी असली और नकली में फर्क करना कठिन बना देते हैं। इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है।

"न्यायपालिका को उन नए साइबर खतरों के अनुरूप ढलना होगा जो एक दशक पहले अकल्पनीय थे।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पारंपरिक ढाँचे अब पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने आह्वान किया कि:

o न्यायाधीशों और वकीलों को डिजिटल धोखाधड़ी की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाए।

o साइबर विशेषज्ञों और पुलिस के साथ सहयोग बढ़ाया जाए।

o जनता को कानूनी प्रक्रियाओं की सही जानकारी देकर जागरूक किया जाए।

o न्यायिक दस्तावेज़ों की नकली प्रतियों और पहचान की चोरी पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

सतर्क रहें, भरोसा करने से पहले सत्यापित करें।

मौत तो सिर्फ दैहिक अंत पर स्त्री की हाय, ईश्वर का मौन न्याय

पिंकी कुंडू

मौत तो देह का अंत है, पर स्त्री की हाय आत्मा की थकान से और रूदन से जन्म लेती है। जब वह प्रतिदिन अपने भीतर

थोड़ी-थोड़ी मरती ह और फिर भी संसार के सामने जीवित होने का अभिनय करती है, तब उसकी हाय प्रार्थना बनकर ईश्वर के चरणों तक पहुँचती है, बिना शब्दों के, बिना शिकायत के।

ईश्वर स्त्री की हाय को कभी बद्दुआ नहीं मानते, वो उसे कर्म का लेखा समझते हैं।

जहाँ अन्याय होता है, जहाँ सहनशीलता को कमजोरी समझा जाता है, वहीं से उसका दण्ड रूपी फल धीरे-धीरे आकार लेने लगता है। न तुरंत, न प्रत्यक्ष, पर अचूक। क्योंकि जो पीड़ा मौन में सह ली जाती है, वो समय के गर्भ में न्याय बनकर पलती है।

स्त्री की हाय, किसी का विनाश नहीं चाहती, वो तो संतुलन चाहती है। वो चाहती है कि, जो बोया गया है, वही लौटे।

मौत एक बार को क्षमा हो सकती है, पर स्त्री की हाय ईश्वर का मौन हस्तक्षेप है— जो देर से सही, पर अन्याय को उसके ही भार से झुका देता है। दण्डित कर देता है!

अडूसा, आयुर्वेद में अडूसा वासा या वासाका के नाम से प्रसिद्ध

पिंकी कुंडू

यह एक अत्यंत उपयोगी और लोकप्रिय औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से श्वसन रोगों, ज्वर, त्वचा समस्याओं और सूजन से संबंधित रोगों में किया जाता रहा है। अडूसा की पहचान इसकी विशिष्ट गंध और कड़वे स्वाद से होती है। इस पौधे के सभी भाग पत्तियाँ, फूल, जड़, बीज, गोंद और दूधिया रस (दूधी) औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुउपयोगी औषधि माना गया है।

अडूसा के प्रकार आयुर्वेद में अडूसा के दो प्रमुख भेद बताए गए हैं।

* श्वेत अडूसा – यह सामान्य रूप से उपलब्ध होता है और अधिकतर औषधीय उपयोग में लिया जाता है,
* कृष्ण अडूसा – इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है और यह दुर्लभ माना जाता है।

श्वसन रोगों में अडूसा के लाभ अडूसा विशेष रूप से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, काली खांसी और अन्य श्वसन संक्रमणों में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके पत्तों या पाउडर को शहद के साथ सेवन करने से कफ बाहर निकलने में सहायता मिलती है। अडूसा में मौजूद सक्रिय तत्व वायुमार्ग से बलगम के स्राव को बढ़ावा देकर सांस नलियों को साफ करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे स्वास रोगों की रामबाण औषधि कहा गया है। नियमित रूप से अडूसा काढ़ा लेने से पुराने श्वसन रोगों में भी राहत देखी जाती है।

गठिया, जोड़ों के दर्द और सूजन में उपयोग अडूसा में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे गठिया और गाउट जैसे रोगों में उपयोगी बनाते हैं। यह

* जोड़ों के दर्द
* सूजन
* अकड़न

को कम करने में सहायक होता है। इसके एंटीस्पास्मोडिक गुण मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को शांत करने में मदद करते हैं।

त्वचा रोगों में अडूसा का प्रयोग अडूसा त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए एक प्रभावी घरेलू औषधि है।

* ताजे पत्तों का पेस्ट लगाने से फोड़े-फुंसी, अल्सर, दर्द और सूजन में राहत मिलती है।
* अडूसा पाउडर को शहद के साथ प्रभावित स्थान पर लगाने से इसके जीवाणुरोधी गुण दाद, खुजली और त्वचा पर होने वाले चकत्तों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

बुखार में लाभ अडूसा का पेस्ट, पाउडर या जड़ का काढ़ा इसके ज्वरनाशक गुणों के कारण शरीर के तापमान को कम करने में सहायक होता है। पुराने या बार-बार आने वाले बुखार में भी आयुर्वेद में इसका प्रयोग बताया गया है।

अडूसा कब लगाएँ अडूसा एक सदाबहार झाड़ीदार पौधा है, जिसे साल में दो मुख्य समय पर लगाया जा सकता है—

* फरवरी–मार्च (वसंत ऋतु) – सबसे उत्तम
* जुलाई–अगस्त (बरसात का मौसम) – दूसरा अच्छा समय
* अत्यधिक ठंड (दिसंबर–जनवरी) में बीज अंकुरण कमजोर रहता है।

अडूसा कैसे लगाएँ अडूसा को तीन तरीकों से उगाया जा सकता है

1. बीज से
2. कलम (कटिंग) से
3. पौधे से

बीज की जानकारी

* अडूसा के बीज छोटे, हल्के भूरे रंग के होते हैं

* बीज फूल आने के बाद फल (कैप्सूल) में बनते हैं
* बीजों की अंकुरण क्षमता 6–8 महीने तक अच्छी रहती है

बीज बोने की विधि

* बीज बोने से पहले 6–8 घंटे सामान्य पानी में भिगो दे
* 1 भाग मिट्टी + 1 भाग गोबर की खाद + 1 भाग रेत मिलाकर नर्सरी ट्रे या गमले में भरें
* बीज ऊपर से 0.5–1 सेमी गहराई में बोए
* हल्की सिंचाई करें, मिट्टी नम रखें
* 10–15 दिन में अंकुरण शुरू हो जाता है

जब पौधा 4–5 इंच का हो जाए, तब उसे मुख्य गमले या जमीन में रोपित करें।

कटिंग से अडूसा लगाना

* 6–8 इंच लंबी अर्ध-कठोर टहनी लें
* नीचे के पत्ते हटा दें
* टहनी को रेतीली दोमट मिट्टी में लगाएँ
* हल्की सिंचाई करें
* 15–20 दिन में जड़ें बन जाती हैं

कलम से लगाए पौधे जल्दी तैयार होते हैं और औषधीय उपयोग के लिए बेहतर माने जाते हैं।

पौधे से रोपण

* नर्सरी से स्वस्थ पौधा लें
* जड़ को नुकसान न पहुँचाते हुए रोपाई करें
* तुरंत हल्का पानी दें

गमले में अडूसा कैसे लगाएँ

* गमले का आकार: 12–14 इंच (एक पौधे के लिए)
* नीचे जल निकास छेद अवश्य हो

मिट्टी मिश्रण:

* दोमट मिट्टी
* 30% गोबर की खाद / वर्मीकम्पोस्ट
* 20% रेत
* 10% कोकोपीट

धूप

4–6 घंटे धूप पर्याप्त

बहुत तेज गर्मी में हल्की छाया लाभदायक

सिंचाई

* सप्ताह में 2–3 बार (मौसम अनुसार)
* जलभराव से बचाएँ

खाद

* हर 30–40 दिन में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट
* वर्ष में 1–2 बार नीम खली देना लाभकारी

कटाई-छँटाई

* 2–3 महीने बाद ऊपर की टहनियाँ काटें
* इससे पौधा झाड़ीदार और घना बनता है
* कटी टहनियाँ पुनः कलम के काम आती हैं

पत्तियाँ कब उपयोग योग्य होती हैं

* रोपण के 5–6 महीने बाद पत्तियाँ औषधीय उपयोग के लिए तैयार
* हमेशा परिपक्व और स्वस्थ पत्तियाँ ही तोड़ें

रोग व सावधानियाँ

* अत्यधिक पानी से जड़ सड़न हो सकती है
* पत्तियों पर कीट दिखें तो नीम तेल का छिड़काव करें
* रासायनिक कीटनाशक से बचें

सहजन के पत्तों से जोड़ों का दर्द कम

पिंकी कुंडू

आजकल घुटनों और जोड़ों में दर्द व सूजन की समस्या बहुत आम हो गई है। बढ़ती उम्र, गलत खानपान और कमजोरी के कारण हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं।

ऐसे में आयुर्वेद में सहजन (मोरिंगा) के पत्तों को बहुत फायदेमंद माना गया है।

सहजन के पत्तों के फायदे:

* हड्डियों को मजबूती देते हैं
* जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत
* शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी करने में मदद
* नसों और मांसपेशियों को ताकत

कैसे करें उपयोग:

* सहजन के ताजे पत्तों की सब्जी बनाएं
* हफ्ते में 2–3 बार भोजन में शामिल करें
* दाल या सूप में भी पत्तों का उपयोग किया जा सकता है

किन लोगों को ज्यादा लाभ:

* घुटनों के दर्द से परेशान लोग
* जोड़ों में सूजन और अकड़न वाले
* कमजोर हड्डियों की समस्या वाले

नियमित रूप से सहजन के पत्तों का सेवन करने से हड्डियों को पोषण मिलता है और जोड़ों का दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है।

पुराना नजला और जुकाम का देशी इलाज

पिंकी कुंडू

वैज्ञानिक कारण:

* काली मिर्च में मौजूद piperine respiratory system को stimulate करता है।
* हल्दी वाले दूध में curcumin सूजन कम करने और immunity support करने में मदद करता है।
* बताशे से हल्की energy मिलती है, जिससे शरीर को ठंड में सहारा मिलता है।

आयुर्वेदिक कारण:

* आयुर्वेद में काली मिर्च और हल्दी को कफ नाशक माना गया है।
* ये शरीर की जमी हुई ठंड और बलगम को संतुलित करने में सहायक माने जाते हैं।

फायदे:

* सर्दी-जुकाम में राहत
* नजले की शिकायत कम हो सकती है
* गले में आराम मिलता है
* immunity को support
* शरीर में गर्माहट आती है

हानि, सावधानी:

* अस्थमा का इलाज नहीं है
* ज्यादा मात्रा से जलन हो सकती है
* acidity वालों को सावधानी
* बच्चों को न दें
* लंबे समय तक रोज़ न लें

कोलेस्ट्रॉल पर नया शोध: वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या समझना ज़रूरी है

हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बनी पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करने को कहा है। नए आँकड़े यह संकेत देते हैं कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों में थोड़ा अधिक कोलेस्ट्रॉल होना आवश्यक नहीं कि हानिकारक ही हो। बल्कि, ऐसे लोगों में दीर्घायु (लंबा जीवन) और कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम कम होने की संभावना देखी गई है।

अब तक उच्च कोलेस्ट्रॉल को मुख्यतः हृदय रोग से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन नए शोध बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए कई आवश्यक कार्य करता है—

यह कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक है
हार्मोन निर्माण के लिए आवश्यक है
और प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाए रखने में भूमिका निभाता है

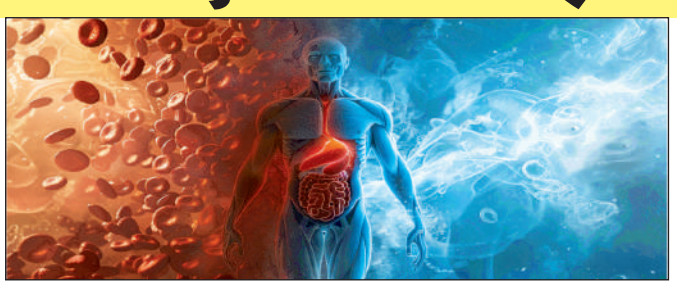

वरिष्ठ आयु में शरीर की मरम्मत क्षमता और रोग-प्रतिरोधक शक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का संतुलित स्तर शरीर को भीतर से सहारा दे सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज़ किया जाए या बिना सलाह के दवाइयाँ छोड़ दी जाएँ। बल्कि संदेश यह है कि अत्यधिक कम कोलेस्ट्रॉल भी हमेशा लाभकारी नहीं होता—खासकर बुज़ुर्गों में।

पहले यह माना जाता था कि कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो, उतना अच्छा। लेकिन अब प्रमाण यह बताते हैं कि मध्यम स्तर कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए संतुलित सुझाव:

* नियमित लिपिड प्रोफाइल जाँच कराते रहें
* अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवा या आहार में बदलाव करें
* संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें
* केवल रिपोर्ट के अंकों से नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य से निर्णय लें

जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यह समझ विकसित हो रही है कि स्वास्थ्य का रास्ता डर से नहीं, बल्कि संतुलन, समझ और जागरूकता से होकर जाता है—विशेषकर जीवन के इस अनुभवी चरण में।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी चिकित्सीय निर्णय के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें।

धनिया के बीज आयुर्वेद में पाचन तंत्र

पिंकी कुंडू

आजकल खराब खान-पान, तली-भुनी चीज़ें, बाहर का खाना और अनियमित दिनचर्या की वजह से गैस, अपच, पेट फूलना और भारीपन आम समस्या बन चुकी है। अगर आप भी बार-बार पेट की इन दिक्कतों से परेशान रहते हैं, तो रसोई में रखा धनिया का बीज आपके बहुत काम आ सकता है।

धनिया के बीज आयुर्वेद में पाचन तंत्र को मजबूत करने वाली एक बेहद सरल और असरदार औषधि माने जाते हैं। इसका नियमित और सही तरीके से सेवन पेट को अंदर से साफ और शांत रखता है।

धनिया के बीज के प्रमुख फायदे

* पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं
* पेट की गैस और अफारे में राहत देते हैं
* खाना जल्दी और सही तरीके से पचाने में मदद करते हैं
* आंतों की सफाई करते हैं
* पेट की जलन और भारीपन कम करते हैं
* कब्ज की समस्या में भी सहायक होते हैं

सेवन करने का आसान तरीका

* रात को 1 चम्मच धनिया के बीज एक गिलास पानी में भिगो दें
* सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पी लें
* चाहें तो बीज हल्के चबाकर भी खा सकते हैं

जरूरी सावधानियां

* ज्यादा मात्रा में सेवन न करें
* बहुत ठंडी तासीर वालों को सीमित मात्रा में लेना चाहिए
* किसी गंभीर पेट रोग में डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है

अगर आप रोज़ाना पेट को हल्का, साफ और स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस देसी नुस्खे को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। सरल है, सस्ता है और पूरी तरह प्राकृतिक है।

कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल), आयुर्वेद में इसके रेचक (Laxative) और वात-शामक गुणों के कारण 'एरण्ड तेल' कहा जाता है, जाने

कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) पेट की सफाई और वात दोष से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन औषधि माना जाता है। प्रमुख आयुर्वेदिक लाभ:

1. पेट के लिए (पाचन और कब्ज),

* प्राकृतिक रेचक: यह कब्ज (Constipation) के लिए रामबाण है। यह आंतों की गतिविधियों को तेज करता है और मल को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है।
* पेट की सफाई (Virechana): आयुर्वेद में पंचकर्म के दौरान शरीर के शोधन (Detox) के लिए अक्सर अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है।

१. जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में

* वात नाशक: आयुर्वेद के अनुसार, जोड़ों का दर्द 'वात' के असंतुलन से होता है। अरंडी का तेल तासीर में गर्म होता है, इसलिए इसकी मालिश से गठिया (Arthritis), सूजन और मांसपेशियों के दर्द में बहुत राहत मिलती है।
* सूजन कम करना: इसमें मौजूद 'रिसिनोलिक एसिड' सूजन को कम करने में प्रभावी है।

३. त्वचा की देखभाल

* गहरी नमी (Deep Moisturizer): यह त्वचा की गहराई तक जाकर उसे हाइड्रेट करता है, जिससे रूखी त्वचा, फटी एड़ियां और फटे होंठ ठीक होते हैं।
* एंटी-एजिंग: यह कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे झुर्रियां (Wrinkles) और महीन रेखाएं कम होती हैं।
* घाव भरना: इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण छोटे-मोटे घावों और त्वचा के संक्रमण को ठीक करने में मदद करते हैं।

4. बालों के लिए फायदेमंद,

* बालों की ग्रोथ: स्कैल्प पर इसकी मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे बाल घने और लंबे होते हैं।
* डैंड्रफ से राहत: इसके एंटी-फंगल गुण रूसी को कम करने और सिर की खुजली मिटाने में सहायक हैं।
* पलकें और भौहें: इसे पलकों (Eyelashes) और भौहों (Eyebrows) पर लगाने से वे घनी और काली होती हैं।

5. अन्य लाभ

* मासिक धर्म में राहत: पेट के निचले हिस्से पर हल्के गर्म अरंडी तेल की मालिश करने से पीरियड्स के दर्द (Cramps) में आराम मिल सकता है।
* प्रसव पीड़ा (Labor Induction): पारंपरिक रूप से इसका उपयोग प्रसव को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता रहा है, लेकिन यह केवल चिकित्सकीय देखरेख में ही होना चाहिए।

अरंडी (Castor) का तेल

इसके बीज आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इसे आमतौर पर 'कैस्टर ऑयल' के नाम से जाना जाता है।

अरंडी के मुख्य फायदे और इस्तेमाल के तरीके:

1. पेट और कब्ज के लिए रामबाण अरंडी का तेल एक प्राकृतिक लैक्सेटिव (Laxative) है। यह आंतों की गतिविधि को बढ़ाकर पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करने में मदद करता है।
* कैसे इस्तेमाल करें: रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर पिएं।

१. जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत इसमें रिसिनोलेइक एसिड (Ricinoleic acid) होता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह गठिया (Arthritis) और जोड़ों के दर्द को कम करने में बहुत प्रभावी है।

* कैसे इस्तेमाल करें: तेल को हल्का गुनगुना करके प्रभावित जगह पर मालिश करें।

३. बालों की ग्रोथ और मजबूती अरंडी का तेल बालों को घना, काला और मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और डैंड्रफ को भी खत्म करता है।

* कैसे इस्तेमाल करें: इसे नारियल या बादाम के तेल के साथ मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं।

4. त्वचा (Skin) के लिए फायदेमंद

* मुंहासे: इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं।
* झुर्रियां: यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा जवान दिखती है।
* फटी एड़ियां: रात को फटी एड़ियों पर इसे लगाने से वे जल्दी कोमल हो जाती हैं।

५. घाव भरने में सहायक यह त्वचा पर एक सुरक्षात्मक लेयर बनाता है और ऊतकों (tissues) के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे चोट या घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं।

कुछ जरूरी सावधानियां:

* गर्भवती महिलाएं: बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि यह लेबर पेन (प्रसव पीड़ा) को उत्तेजित कर सकता है।
* मात्रा का ध्यान: इसका अधिक सेवन करने से दस्त, उल्टी या पेट में मरोड़ हो सकती है।
* एलर्जी: त्वचा पर लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें।

सावधानी:

1. सेवन की मात्रा: आंतरिक रूप से सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से दस्त, पेट में ऐंठन या उल्टी हो सकती है।
१. गर्भावस्था: गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
३. तासीर: इसकी तासीर गर्म और भारी होती है, इसलिए इसे हमेशा संयम से उपयोग करें।

हाथ-पैर सुन्न होने का देसी घरेलू उपाय

पिंकी कुंडू

अगर आपके हाथ-पैर बार-बार सुन्न हो जाते हैं, झनझनाहट महसूस होती है या लंबे समय तक बैठने या सोने के बाद सुन्नपन बना रहता है, तो यह संकेत नसों की कमजोरी या पोषण की कमी का हो सकता है।

ऐसे में अलसी के बीज एक बेहद सरल, सस्ते और देसी उपाय के रूप में काम आते हैं। आयुर्वेद में अलसी को नसों को मजबूत करने वाला माना गया है।

अलसी के बीज के फायदे:

* नसों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं
* हाथ-पैरों की झनझनाहट और सुन्नपन कम करने में सहायक
* रक्त संचार को बेहतर बनाने में मददगार
* शरीर में अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में उपयोगी

इस्तेमाल करने का सही तरीका:

* रोज़ाना 1 चम्मच अलसी के बीज खाएँ
* चाहें तो हल्के भुने हुए बीज भी ले सकते हैं
* नियमित सेवन से बेहतर परिणाम मिलते हैं

ध्यान रखने योग्य बातें:

* अलसी सीमित मात्रा में ही लें
* लंबे समय से समस्या बनी हो तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें
* गर्भवती महिलाएँ सेवन से पहले सलाह लें

यह देसी घरेलू उपाय रोज़मर्रा में आसानी से अपनाया जा सकता है और नसों की सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है।

हिन्दू शास्त्रों में वर्णित पंचकन्याओं का परिचय

पिंकी कुंडू

हिंदू धर्मशास्त्रों में पंचकन्या (पाँच कन्याएँ) को विशेष महत्व प्राप्त है। ये पाँच महान नारियाँ हैं जिनका स्मरण मात्र से महापातक (बड़े पाप) नष्ट हो जाते हैं।

यह एक प्रसिद्ध श्लोक में वर्णित है:-

अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा।
पंचकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनाशिनीः॥

(अर्थः अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी – इन पंचकन्याओं का नित्य स्मरण करने से महान पापों का नाश होता है।)

ये पंचकन्याएँ रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। इन्हें विवाहित होने और संतान प्राप्ति के बावजूद ऱचिर कुमारीऱ या पवित्र कन्या माना जाता है, क्योंकि इनकी पवित्रता, धैर्य, पतिव्रत धर्म और कर्तव्यनिष्ठा अतुलनीय है। विवाहित महिलाएँ प्रातःकाल इनका स्मरण करके प्रणाम करती हैं, जिससे सौभाग्य और पाप नाश होता है।

1. अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में बनाई गई। इंद्र के छल से भ्रमित होने पर गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गईं, लेकिन भगवान राम के स्पर्श से मुक्त हुईं। पतिव्रता और पवित्रता की प्रतीक।

2. द्रौपदी महाभारत की नायिका, पाँच पांडवों (युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव) की पत्नी। द्रुपद राजा के यज्ञ से उत्पन्न हुईं, इसलिए याज्ञसेनी भी कहलाती हैं। चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। धैर्य, न्याय और स्त्री शक्ति की मिसाल।

3. कुंती महाभारत में पांडवों की माता। मूल नाम पृथा, कुंतीभोज द्वारा गोद ली गईं। पांडु की पत्नी। दुर्वासा ऋषि से प्राप्त मंत्र से धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया (कर्ण पूर्व जन्म में सूर्य से)। ममता, त्याग और कर्तव्यपरायणता की प्रतीक।

4. तारा रामायण में वानरराज बाली की पत्नी। अत्यंत बुद्धिमती और समझदार। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव की पत्नी बनीं। बुद्धि, विवेक और धैर्य की देवी के रूप में पूजी जाती हैं।

5. मंदोदरी रामायण में रावण की पत्नी। अप्सरा हेमा और मयासुर की पुत्री। पतिव्रता, शिवभक्त और धर्मपरायण। कई बार रावण को सीता वापस करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने नहीं मानी। सतीत्व और सद्गुणों की आदर्श।

ये पंचकन्याएँ कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और मर्यादा पर अडिग रहीं, इसलिए इन्हें आदर्श नारी का प्रतीक माना जाता है। इनका दैनिक स्मरण जीवन में सुख-शांति और पाप मुक्ति प्रदान करता है।

हनुमान जी के 5 सगे भाई

पिंकी कुंडू

हम में से अधिकतर लोग आज तक नहीं जानते हैं की वानरराज केसरी और अजनी माता के कितने पुत्र थे। हम सिर्फ हनुमान जी के बारे मे ही जानते हैं क्योंकि हनुमान जी, रुद्रावतार, राम भक्त, अंजनी नंदन, केसरी नंदन, पवन देव सुत, सूर्य देव शिष्य, शनि देव वरदानी और अन्य कई नामों से धार्मिक ग्रंथों की गाथा में नजर आते हैं। आज हम आपको उनके भाईयों के नामों से परिचित करवा रहे हैं, जाने

1. मैतिली (मैत्रेय)
2. शरत
3. गंधमादन
4. अंजन (या अंजनिपुत्र नाम से अलग संदर्भों में)
5. रामभद्र

महत्वपूर्ण बात शास्त्रों और पुराणों में हनुमान जी के भाइयों के नाम अलग-अलग ग्रंथों में भिन्न मिलते हैं। सबसे अधिक प्रसिद्ध और पूजित नाम हनुमान जी का ही है, जबकि उनके भाइयों का वर्णन सीमित रूप में आता है। कुछ ग्रंथों में केवल 1–2 भाइयों का ही उल्लेख मिलता है, जबकि लोककथाओं में पाँच सगे भाइयों की मान्यता प्रचलित है।

स्फटिक माला (Crystal Mala)

पिंकी कुंडू

स्फटिक माला (Crystal Mala) पारदर्शी, ठंडे स्वभाव वाले क्रिस्टल क्वाट्र्ज से बनी एक पवित्र माला है, जो हिन्दू परंपरा में ध्यान, मंत्र जाप (खासकर माँ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा), और ज्योतिषीय लाभों (जैसे शुक्र ग्रह को मजबूत करना, मन को शांत करना, भय दूर करना, धन-ऐश्वर्य प्राप्त करना) के लिए उपयोग होती है, जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी मानी जाती है और इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है,

स्फटिक क्या है? यह एक रंगहीन, पारदर्शी रत्न (क्वाट्र्ज) होता है, जो कांच जैसा दिखता है लेकिन उससे ज़्यादा कठोर होता है.

स्फटिक माला के लाभ (Benefits):

मानसिक शांतिः मन को शांत, एकाग्र और धैर्यवान बनाती है, भय व घबराहट कम करती है.

आध्यात्मिक शक्तिः मंत्रों (जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा) के जाप के लिए उत्तम, जिससे मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और आध्यात्मिक साधना में मदद मिलती है.

ज्योतिषीय लाभः शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और धन-संपत्ति, यश प्राप्त होता है.

स्वास्थ्यः नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है; इसे शरीर पर रखने से बुखार में भी आराम मिल सकता है.

कैसे करें उपयोगः

* मां लक्ष्मी के मंत्र 'ॐ श्री श्री नमः' का जाप करने के लिए इसे गुलाब जल में धोकर, शुक्रवार को अभिमंत्रित करके धारण किया जा सकता है (रात में उतार दें).

* यह माला नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता लाती है और सभी देवी-देवताओं के मंत्रों के जाप के लिए उपयोग की जाती है.

सावधानियाँ:

* असली स्फटिक माला ठंडी होती है; नकली माला से बचें.

* ठंडे मौसम में या ठंडे पानी के संपर्क में आने पर ज़्यादा ठंडक महसूस हो सकती है,

ज़िंदगी हमेशा मुस्कान का नाम नहीं होती। कभी-कभी भीतर इतनी चुप्पी भर जाती है कि आँखें मुस्कुराती रहती हैं पर दिल रोता है।

हम सब के जीवन में ऐसे दिन आते हैं। * जहाँ लोग आसपास होते हैं पर मन अकेला होता है।

* जहाँ बाहर सब कुछ सही होता है, पर अंदर सही नहीं होता।
* जहाँ हम दूसरों के लिए मजबूत होते हैं, पर अपने लिए बेहद कमज़ोर।

उसी दौर में रामायणजी हमारे जीवन में कथा बनकर नहीं, मरहम बनकर आतीं हैं

1. रामजी हमें सिखाते हैं— स्वीकार करो, टूटो मत ऐसा लगता है कि जब हालात हमारे हाथ से निकल रहे होते हैं, जब ज़िंदगी कहती है कि ये भी सहना पड़ेगा, तब रामजी बताते हैं कि "वनवास दुख नहीं, वनवास यात्रा है।"
* हम सीखते हैं कि दर्द भागने के लिए नहीं, दर्द समझने के लिए होता है और
* जो दर्द को समझ लेता है, वो खुद को पा लेता है।

२. सीताजी हमें सिखाती हैं कि सम्मान खो देने से बड़ी हार कोई नहीं जीवन में स्थितियाँ आईं, जहाँ दिल टूटा, भरोसा टूटा, लोग बदल गए पर
* सीताजी की दृढ़ता ने सिखाया कि खामोश रहना कमजोरी नहीं होती कभी-कभी यह सबसे बड़ी ताकत होती है।
* उन्होंने हमें सिखाया कि तुम चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियों में हो, अपने आत्म-सम्मान से कभी समझौता मत करना।

३. भरत और लक्ष्मण ने सिखाया कि प्यार "त्याग" का नाम है कुछ रिश्तों ने दूरी देकर भी साथ दिया। कुछ ने पास रहकर भी जख्म दिए। तब समझ आया कि साथ हमेशा नज़दीकियों से नहीं मापा जाता, भावनाओं से मापा जाता है।

4. हनुमानजी हमें हमारी शक्ति याद दिलाते हैं हम कई बार ख़ुद से कहते हैं कि-अब बस। हम और नहीं कर पाएंगे। इतनी ताकत मुझमें नहीं है लेकिन हनुमानजी धीरे से कान में कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने शक्तिशाली हो और सच में, हम अपनी ताकत को फिर से पाना शुरू कर देते हैं।

5. रावण हमें हमारी सबसे खतरनाक बीमारी बताता है वो बीमारी थी अहंकार। अहंकार सिर्फ़ जीत के बाद नहीं आता, कभी-कभी दुख के समय भी आ जाता है-"क्यों मेरे साथ? मैं ही क्यों?" पर रावण हर बार याद दिलाता है कि जितना ऊँचा बनोगे, उतना झुकना सीखो। वरना ऊँचाई से गिरना बहुत दर्द देता है।

6. *रामायणजी हमें अंदर से हील (Heal) ही नहीं करती बल्कि हम अपने को हील (Heal) कैसे करें- ये सिखाती भी हैं।
* रामायण ने हमारे ज़ख्म छुपाए नहीं, उन्हें स्वीकार करना सिखाया।
* रामायण ने हमारी तकलीफ खत्म नहीं की, हमें मजबूत बना दिया कि हम उन्हें सह सकें।
* रामायणजी ने कहा:
* टूटे हो? टूटने दो—पर हारने मत देना खुद को।
* रोने का मन है? रो लो—पर उम्मीद मत मरने देना।
* गिर गए? गिरो—पर उठना मत भूलना।
* हीलिंग का मतलब दर्द मिट जाना नहीं,
* हीलिंग का मतलब है दर्द के साथ जीना सीख जाना, मुस्कुराना सीख जाना।

"यज्ञ और हवन में अंतर"

पिंकी कुंडू

हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन दोनों ही अग्नि आधारित महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिनमें मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति दी जाती है। दोनों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, वातावरण शुद्ध करना और मनोकामनाएं पूरी करना है। हालांकि, आम बोलचाल में इन्हें एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन शास्त्रों और परंपरा के अनुसार इनमें स्पष्ट अंतर है।

मुख्य अंतरः-

यज्ञ (Yajna/Yagya):-

* यह एक व्यापक और वैदिक अनुष्ठान है, जो बड़े पैमाने पर किया जाता है।

* इसमें कई देवताओं का आह्वान, वेद मंत्रों का उच्चारण, ऋत्विक (पुरोहितों) की उपस्थिति और दक्षिणा (दान) अनिवार्य होती है।

उद्देश्यः- विशेष मनोकामना पूर्ति, लोक कल्याण, अनिष्ट निवारण या सामाजिक/सार्वजनिक लाभ (जैसे वर्षा, विजय आदि)।

समयः- लंबा (घंटों, दिनों या महीनों तक) और नियम कठिन।

उदाहरणः- अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या बड़े धार्मिक आयोजन।

हवन :-

* यह यज्ञ का छोटा या लघु रूप है, जो घरेलू या व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है।

* मुख्य रूप से हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं को हवि (आहुति सामग्री जैसे घी, जड़ी-बूटियां) पहुंचाने की प्रक्रिया।

उद्देश्यः- शुद्धिकरण, गृह शांति, वास्तु दोष निवारण, नवग्रह शांति या दैनिक पूजा का हिस्सा।

समयः- छोटा (कुछ घंटे) और सरल।

उदाहरणः- गृह प्रवेश, विवाह या पूजा के अंत में किया जाने वाला हवन।

यज्ञ और हवन के लिए नियम
* यज्ञ कठिन, कई ऋत्विक और दक्षिणा आवश्यक
* हवन सरल, घर का सदस्य भी कर सकता है।

यज्ञ और हवन के उद्देश्य
* यज्ञ लोक कल्याण, विशेष संकल्प
* हवन शुद्धि, दैनिक पूजा, छोटी कामनाएं।

आवश्यक तत्व देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा मुख्यतः अग्नि और हवि।

संक्षेप मेंः- हवन यज्ञ का एक अंग या सरलीकृत रूप है। आधुनिक समय में ज्यादातर घरेलू अनुष्ठानों में हवन ही किया जाता है, जबकि बड़े यज्ञ दुर्लभ हैं। दोनों से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

जप माला के नियम और सावधानीयाँ

पिंकी कुंडू

माला शब्द दो अक्षरों से बना है—मा + ला। 'मा' माने लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान; 'ला' माने जिसमें लीन रहे; इसलिए 'लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान जिसमें लीन रहते हैं वह है माला।

साधना में जप माला बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। जब जप अधिक संख्या में करना हो तो जप माला रखना अनिवार्य है। भगवान का स्मरण और नाम-जप की गिनती करने के कारण साधक को इसे अपने प्राणों के समान प्रिय मानना चाहिए।

एक बार वृन्दावन में दो संतों में लड़ाई हो गयी। एक संत ने दूसरे के लिए कहा—'इसने मेरा हीरा चुरा लिया है।' दूसरे ने कहा—'इन्होंने मेरा पारस चुरा लिया है।' मामला अदालत में गया। दोनों ने अपनी-अपनी बात कही। जज ने पूछा—'तुमको हीरा कहां से मिला?' पहले संत ने उत्तर दिया—'हमको हमारे गुरु ने दिया था।' जज ने पूछा—'कहां रखते थे?' संत ने ने कहा—'अपने कण्ठ में बांध कर रखता था।' (तुलसी के मनके को वैष्णव संत 'हीरा' कहते हैं)

दूसरे संत से जज ने पूछा—'तुमको पारस कहां से मिला जो इसने चुरा लिया?' (भगवान के प्रसाद को संत 'पारस' कहते हैं)। दूसरे संत ने उत्तर दिया—'मुझको मन्दिर से रोज 'पारस' मिलता था, इसने बंद करा दिया।'

इस प्रकार संतों में भगवान का प्रसाद 'पारस' और माला 'मणि' मानी जाती है। जप माला में मणि, मनिया या दाने पिरोये जाने के कारण इसे 'मणि माला' कहते हैं। पर आजकल लोग जप माला को लटकाये-लटकाये फिरते हैं, जूठे हाथों से छू लेते हैं या जेब में रख लेते हैं।

दूसरे की माला से जप क्यों नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को अपनी जप माला अलग रखनी चाहिए। दूसरे की माला पर जप नहीं करना चाहिए। जप की माला पर जब एक ही मन्त्र जपा जाता है, तो उसमें उस देवता की प्राण-प्रतिष्ठा हो जाती है, माला चैतन्य हो जाती है। फिर उस माला पर एक ही मन्त्र का जप किया जाए तो धीरे-धीरे मन्त्र की चैतन्य शक्ति साधक के शरीर में प्रवेश करने लगती है। तब वह माला साधक का कल्याण करने वाली हो जाती है इसलिए अपनी जप माला न किसी दूसरे को देनी चाहिए और न ही किसी दूसरे की माला पर जप करना चाहिए। लेना-देना तो क्या दूसरों को अपनी माला दिखानी भी नहीं चाहिए। माला की पवित्रता की जितनी रक्षा आप करेंगे, उतनी ही पवित्रता आपके जीवन में आयेगी।

जप माला के साथ न करें ये काम?

* माला लोगों को दिखाने की चीज नहीं है बल्कि धन की भांति साधक को इसे गुप्त रखना चाहिए।

* माला की पवित्रता का साधक को पूरा ध्यान रखना चाहिए।

* जप माला को केवल जप की गिनती करने वाला साधन न समझ कर उसका पूरा आदर करना चाहिए।

* अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छूना चाहिए

* बायें हाथ से जप माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

* माला को पैर तक लटका कर नहीं रखना चाहिए।

* माला को जहां कहीं भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। या तो उसे जपमाली में या किसी डिब्बी में रखकर शुद्ध स्थान पर रखें।

माला जप करते समय रखें इन बातों का ध्यान?

* जप के लिये माला को हृदय के सामने अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें, तर्जनी अंगुली न लगावें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें।

* जप करते समय माला ढकी हुई होनी चाहिए।

* जब तक एक माला पूरी न हो, बीच में बोलना नहीं चाहिए, दूसरों की ओर देखना नहीं चाहिए, इशारे नहीं करना चाहिए।

* यदि जप करते समय किसी कारण बीच में उठना पड़े तो माला पूरी करके ही उठना चाहिए और दुबारा जप के लिए बैठना हो तो आचमन करके ही जप शुरु करना चाहिए।

विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार माला में भेद होता है? जप माला अनेक वस्तुओं की होती है, जैसे तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा (पद्मबीज), स्फटिक, हल्दी, लाल चंदन, शंख, जीवपुत्रक, मोती, मणि, रत्न, सुवर्ण, मूंगा, चांदी और कुशमूल। इन सभी के मणियों (दानों) से माला तैयार की जाती है।

* इनमें वैष्णवों के लिए तुलसी और स्मार्त, शैव व शाक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गयी है।

* मनुष्य की जितनी कामना होती हैं, उनके उतने ही मन्त्र होते हैं और उतने ही देवता। आजकल लोग एक ही माला पर सभी देवताओं के मन्त्र जप लेते हैं, यह माला की मर्यादा की अवहेलना है। विभिन्न देवताओं की अलग-अलग मालाएं होती हैं।

* जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले मन्त्र कमलगट्टे की या लाल चंदन की माला पर

* विष्णु, श्रीकृष्ण या श्रीराम के मन्त्र तुलसी माला पर

* शंकर, हनुमान, दुर्गा आदि के मन्त्र रुद्राक्ष की माला पर

* मां बगलामुखी का जप हल्दी की माला पर आदि।

जपमाला बनाते या खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान? माला बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज की माला में दूसरी चीज न लगायी जाए।

* माला के दाने छोटे-बड़े न हों।

* जपमाला में पूरे 108 दाने होने चाहिए, कम या अधिक नहीं।

* विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार भी मालाओं में भेद होता है

* शान्तिकर्म में श्वेत,

* वशीकरण में लाल,

* अभिचार में कृष्ण और मोक्ष व ऐश्वर्य के लिए रेशमी सूत की माला अच्छी मानी जाती है।

* शात्रों में वर्ण के अनुसार माला पिरोने के लिए सूत का रंग चुना जाता था।

* जैसे ब्राह्मण के लिए सफेद रंग का सूत,

* क्षत्रिय के लिए लाल,

* वैश्य के लिए पीला और

* शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का सूत माला बनाने में प्रयोग करने का विधान है।

* सोने के तार में भी माला पिरोयी जा सकती है।

विकास की पटरी पर कुचला वन्यजीवन

- डॉ सत्यवान सौरभ

दिसंबर 2025 में असम के होजाई ज़िले में सात हाथियों—जिनमें शावक भी शामिल थे—की रेल दुर्घटना में हुई मृत्यु कोई साधारण हादसा नहीं थी। यह घटना भारत के विकास मॉडल और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बीच बढ़ते टकराव का प्रतीक बनकर सामने आई। तेज़ रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर न केवल हाथियों की जान गई, बल्कि इंजन और कई डिब्बों के पटरी से उतरने से यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसी घटनाएँ केवल वन्यजीवों के लिए ही नहीं, बल्कि मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा हैं।

हाथी भारत का "राष्ट्रीय धरोहर पशु" है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में संरक्षित है। इसके बावजूद, हर वर्ष रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौतें यह सवाल उठाती हैं कि क्या हमारा विकास सचमुच सतत है, या वह प्रकृति की कीमत पर आगे बढ़ रहा है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में सैकड़ों हाथी ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं, जिनमें असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं।

भारत में रेलवे लाइनों, राष्ट्रीय राजमार्गों, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों और अन्य रेखीय अवसंरचनाओं का तेज़ी से विस्तार हुआ है। यह विस्तार आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक माना गया, किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये परियोजनाएँ वनों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों को बिना पर्याप्त पारिस्थितिक योजना के काटती हुई आगे बढ़ती हैं। रेलवे ट्रैक विशेष रूप से घातक सिद्ध होते हैं क्योंकि ट्रेनें न तो दिशा बदल सकती हैं और न ही अचानक रुक सकती हैं। दूसरी ओर, हाथियों की दृष्टि क्षमता सीमित होती है और उनका भारी शरीर तेज़ प्रतिक्रिया में बाधक बनता है।

हाथी बड़े भूभाग में विचरण करने वाले जीव हैं और भोजन, पानी तथा प्रजनन के लिए पारंपरिक प्रवासी मार्गों पर निर्भर रहते हैं। जब रेलवे लाइनें इन गलियारों को काट देती हैं, तो हाथियों के सामने ट्रैक पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दुर्भाग्य से, अनेक दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र आज भी आधिकारिक रूप से "हाथी गलियारे" घोषित नहीं किए गए हैं। असम का होजाई क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ वर्षों से हाथियों की नियमित आवाजाही के बावजूद कानूनी संरक्षण का अभाव रहा है।

दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ट्रेनों की अत्यधिक गति भी है। पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भी ट्रेनों की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है। इतनी गति पर हाथियों को देखकर ट्रेन रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। अस्थायी गति प्रतिबंध और चेतावनियाँ प्रायः कागज़ी साबित होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेलवे संचालन में अभी भी पर्यावरणीय सुरक्षा की तुलना में समय और दक्षता को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

दृश्यता की समस्या भी इन दुर्घटनाओं को बढ़ाती है। अधिकांश हाथी-रेल टकराव रात या तड़के होते हैं, जब कोहरा, वर्षा या घनी वनस्पति के कारण ट्रेन चालकों की दृष्टि सीमित हो जाती है। असम और पूर्वोत्तर भारत में यह स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ मौसम की अनिश्चितता सामान्य बात है। इसके अतिरिक्त, रेलवे ट्रैक स्वयं हाथियों को आकर्षित करते हैं। यात्रियों द्वारा फेंका गया खाद्य अपशिष्ट, नमकयुक्त मिट्टी और पटरियों के आसपास पकती फसलें हाथियों को जोखिम वाले क्षेत्रों की ओर खींचती हैं, विशेषकर फसल कटाई के मौसम में।

रेलवे ट्रैक का डिज़ाइन भी कई बार समस्या को बढ़ाता है। ऊँचे तटबंध, कंक्रीट की दीवारें और बाड़ें हाथियों को ट्रैक पर फँसा देती हैं। शावक जल्दी बाहर नहीं निकल पाते, जिससे पूरा झुंड धीमा हो जाता है और दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ ही, वन विभाग और रेलवे के बीच समुचित समन्वय की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। गश्ती दल द्वारा हाथियों की उपस्थिति की सूचना अक्सर समय पर रेलवे नियंत्रण कक्ष तक नहीं पहुँच पाती, जिससे दुर्घटनाएँ रोकी नहीं जा पातीं।

हर बड़ी दुर्घटना के बाद जाँच, मुआवज़ा और अस्थायी प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जाते हैं, किंतु ये सभी प्रतिक्रियात्मक उपाय हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन अक्सर औपचारिकता बनकर रह जाता है और परियोजना स्वीकृति के बाद पशु व्यवहार में आए परिवर्तनों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आवश्यकता इस बात की है कि संरक्षण को विकास की राह में बाधा नहीं, बल्कि उसका अनिवार्य हिस्सा माना जाए।

हाथियों की सुरक्षा के लिए सभी ज्ञात प्रवासी गलियारों को कानूनी संरक्षण देना आवश्यक है, चाहे वे पहले से अधिसूचित हों या नहीं। ऐसे सभी क्षेत्रों में स्थायी गति सीमा लागू की जानी चाहिए। तकनीकी समाधान के रूप में AI आधारित इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम, जो हाथियों की गतिविधि पहचानकर समय से ट्रेन चालकों को चेतावनी देते हैं, अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। इन प्रणालियों का सीमित प्रयोग पर्याप्त नहीं है; इन्हें राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए अंडरपास, ओवरपास और मिट्टी के रैंप हाथियों के सुरक्षित पारगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, ऐसे ढाँचों से हाथियों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी संभव है। पटरियों के किनारे फलदार पेड़ों की कटाई, नियमित सफाई और ट्रेनों में शून्य–कचरा नीति अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। "प्लान बी" जैसी योजनाएँ, जिनमें मधुमक्खियों की आवाज़ से हाथियों को दूर रखा जाता है, व्यवहारिक और मानवीय समाधान प्रस्तुत करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि जब संरक्षण को गंभीरता से लिया जाता है, तो विकास और वन्यजीवन के बीच संतुलन संभव है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों ने वन्यजीव पारगमन संरचनाओं और कठोर गति नियंत्रण से दुर्घटनाओं में भारी कमी लाई है। भारत भी इन मॉडलों को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपना सकता है।

हाथियों की मौत केवल नैतिक विफलता नहीं है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी है। ट्रेन दुर्घटनाएँ, मानवीय क्षति, संपत्ति का नुकसान और सेवा बाधाएँ—इन सबकी लागत निवारक उपायों से कहीं अधिक होती है। अंततः, रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत तकनीकी नहीं, बल्कि नीतिगत असफलता का परिणाम है।

भारत को यह तय करना होगा कि उसका विकास प्रकृति को रौंदते हुए आगे बढ़ेगा या उसके साथ सह-अस्तित्व स्थापित करेगा। पर्यावरण–प्रथम इंजीनियरिंग, कानूनी संरक्षण और तकनीकी नवाचार के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रगति की रेलगाड़ी, वन्यजीवन को कुचलती न चले।

ईश्वर के अस्तित्व की मीमांसा: दर्शन और तकनीक की कसौटी पर

पंकज जायसवाल

अभी हाल ही में एक चैनल पर जावेद अख्तर और मुफ़्ती शमाइल नदवी द्वारा क्या ईश्वर विद्यमान है? विषय पर बहस किया गया है और यह विमर्श वैचारिक स्तर पर रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता रहा. उसी के नेपथ्य में मैं नीचे अपना विमर्श प्रस्तुत कर रहा हूं जो यह ढूंढने की कोशिश करेगा कि क्या ईश्वर है? और यदि है तो किस रूप में है?

ईश्वर के अस्तित्व को समझने में अद्वैतवाद दर्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सहायक दृष्टि प्रदान करता है। अद्वैतवाद दर्शन जीव और ब्रह्म को दो अलग-अलग सत्ता नहीं मानता बल्कि उन्हें एक ही सत्य के रूप में स्वीकार करता है। इसका मूल ब्रह्मसूत्र है "अहं ब्रह्मास्मि" और इसका सिद्धांत "तत्त्वमसि" अर्थात तुम वही हो और मैं भी वही ब्रह्म हूँ। इस दर्शन के अनुसार यह पूरा जीव जगत ब्रह्म की माया है जिसे आधुनिक संदर्भ में हम एक प्रकार के मेटावर्स या इल्यूजन के रूप में भी समझ सकते हैं।

अद्वैत कहता है जगत्माया है, जीव मिथ्या है और मोक्ष निष्काम है, जहाँ जगत, जीव और जीवन तीनों का अंततः ब्रह्म में विलय हो जाना है। अब प्रश्न उठता है कि यह ब्रह्म क्या है? तो उत्तर है कि ब्रह्म वही दिव्य ऊर्जा है, जो एक सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस को धारण किए हुए है। इसी दिव्य चेतना को हम अलग-अलग परंपराओं, संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों में अपने-अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। जब मनुष्य ईश्वर की पूजा करता है, तो वह वास्तव में अपने प्रार्थना भाव के माध्यम से इसी दिव्य ऊर्जा से संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है।

चूँकि ज्ञात और अज्ञात पूरा ब्रह्मांड एक ही मूल पदार्थ तरंगों से निर्मित है, इसलिए मनुष्य की प्रार्थना भी उन्हीं तरंगों के माध्यम से पृथ्वी और ब्रह्मांड को संचालित करने वाली चेतना तक पहुँचने का प्रयास करती है ताकि वह इसे सुन सके और संकेत भेज सके या परिस्थितियों में बदलाव कर सके। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे-धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। न्यूटन से लेकर आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक की खोजों ने विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने का ही कार्य किया है। इन वैज्ञानिकों के शोध यह संकेत देते हैं कि केवल पदार्थ ही अंतिम सत्य नहीं है बल्कि उसके पीछे कोई गहरी चेतना कार्य कर रही है।

आधुनिक मेटा-फिजिक्स भी अद्वैत वेदांत के इस वैज्ञानिक दर्शन के समानांतर विचारधारा पर चलती दिखाई देती है। मेटा-भौतिकी के नवीन सिद्धांत यह संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड का मूल कारण पदार्थ नहीं बल्कि उसमें व्याप्त चेतना है। इसी चेतना को अद्वैत वेदांत ब्रह्म कहता है जबकि आधुनिक भौतिकी इसे अंतरिक्ष में व्याप्त तरंग, ऊर्जा या वेव के रूप में समझने का प्रयास करती है। यही तरंग, ऊर्जा या वेव का समुच्चय परमात्मा है जिसे हम भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर मानते हैं, और कण-कण में व्याप्त इसकी सूक्ष्म इकाई को हम ब्रह्म से जुड़ा हुआ प्राण या आत्मा कहते हैं। इसीलिए कण कण में ईश्वर की बात कही भी जाती है ऐसा नहीं कि ईश्वर यूनिवर्स से परे कहीं जाकर बैठा हुआ है.

मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने क्वांटम भौतिकी में अनेक ऐसे विमर्श प्रस्तुत किए जिनके कारण मेटा-भौतिकी को संभावना का विज्ञान भी कहा जाने लगा। इसके बाद आया ऑब्ज़र्वर इफेक्ट का सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी क्वांटम तरंग को मापे जाने पर वह कण की तरह व्यवहार करती है जबकि न देखे जाने पर वह एक ही समय में कई स्थानों पर मौजूद हो सकती है जिसे सुपरपोज़ीशन कहा जाता है। जॉन व्हीलर ने इसे और गहराई से कहा "यदि देखने वाला न हो तो जगत केवल ऊर्जा है".

आइंस्टीन के ऊर्जा सूत्र ने जहाँ पदार्थ और ऊर्जा के अंतर्संबंध को स्पष्ट किया, वहीं सापेक्षता और ऑब्ज़र्वर इफेक्ट ने भौतिकी को उस बिंदु पर ला खड़ा किया जहाँ ब्रह्मांड को समझने के लिए चेतना का अध्ययन अनिवार्य हो गया। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जिस सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस से संचालित हो रहा है, वही ब्रह्म ऊर्जा है। जैसे किसी जीव में प्राण-ऊर्जा की आपूर्ति रुकने पर कोशिकाएँ बिखरने लगती हैं, अंग-तंत्रों का संतुलन टूट जाता है और मृत्यु की अवस्था आती है वैसे ही यदि इस ब्रह्म-ऊर्जा की आपूर्ति रुक जाए तो पूरी कायनात के विघटन और ऊर्जा में विलीन हो जाने की संभावना बन सकती है। ऐसे में केवल जीव ही नहीं बल्कि जगत भी ब्रह्म में विलीन हो सकता है। शायद इसी कारण विभिन्न धर्मों में ईश्वर की पूजा मूलतः एक थैंक्सगिविंग और उस दिव्य चेतना से संवाद का प्रयास है।

भविष्य का निर्माण स्थल: क्यों भारत बना एआई निवेश का केंद्र

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

दुनिया की सत्ता और समृद्धि अब हथियारों या संसाधनों से नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म और डेटा की ताकत से तय हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस नए युग की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुका है, जो वैश्विक संतुलन की दिशा तय कर रही है। ऐसे निर्णायक दौर में भारत खुद को केवल दर्शक नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में स्थापित करने की तैयारी करता दिख रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी वैश्विक टेक दिग्गज कंपनियों द्वारा भारत में कुल 67.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कोई सामान्य आर्थिक खबर नहीं, बल्कि भविष्य की तस्वीर गढ़ने वाला संकेत है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच सामने आई ये प्रतिबद्धताएं बताती हैं कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि एआई युग का सक्रिय निर्माता बनने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है। यह निवेश लहर भारत के डिजिटल आत्मविश्वास, नीतिगत स्थिरता और तकनीकी सामर्थ्य पर वैश्विक भरोसे की ठोस अभिव्यक्ति है।

भारत पहले ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश को तकनीकी नवाचार का मजबूत आधार दिया है। अब जब एआई वैश्विक विकास का इंजन बन चुका है, तब भारत को इसका केंद्र बनाने की तैयारी दिखाई देती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का यह संयुक्त निवेश केवल पूंजी प्रवाह नहीं, बल्कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम के विस्तार का रोडमैप है। इन पहलों से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिलेगी और छोटे व्यवसाय वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। यह निवेश भारत को एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने की नींव रख रहा है।

इस मेगा निवेश यात्रा की शुरुआत गूगल ने की, जिसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 15 अरब डॉलर के निवेश से भारत का अब तक का सबसे बड़ा एआई हब और गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने की घोषणा की। यह परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत होगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और सबसी केबल नेटवर्क पर आधारित होकर टिकाऊ विकास का उदाहरण भी बनेगी। यह केंद्र बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग रिसर्च और क्लाउड सेवाओं को गति देगा। गूगल का यह कदम भारत को वैश्विक एआई वैल्यू चेन में ऊंचा स्थान दिलाने में सहायक होगा और देश को उच्चस्तरीय रिसर्च व डेवलपमेंट का केंद्र बनाएगा।

इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा विस्तार योजना सामने रखी। कंपनी का फोकस हाइपरस्केल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म और डिजिटल सॉवरेनिटी पर आधारित सेवाओं के विकास पर है। माइक्रोसॉफ्ट भारत में बड़े पैमाने पर एआई स्किलिंग प्रोग्राम भी शुरू कर रही है, जिससे लाखों युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। यह पहल केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत को उच्च-गुणवत्ता वाले एआई पेशेवरों का वैश्विक स्रोत बनाएगी। सरकारी और निजी संस्थानों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद डिजिटल समाधान विकसित करना भी इस निवेश का अहम उद्देश्य है।

सबसे बड़ा दांव अमेजन ने खेला है, जिसने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश एआई-आधारित डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स विस्तार, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड सेवाओं और निर्यात को गति देने पर केंद्रित होगा। अमेजन का अनुमान है कि इससे करीब 1.5 करोड़ छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और भारत का निर्यात 80 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। एआई आधारित टूल्स के जरिए सप्लाई चेन, ग्राहक सेवा और उत्पाद प्रबंधन को अधिक कुशल बनाया जाएगा। इससे न केवल व्यापार आसान होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बड़े पैमाने पर सृजित होंगे।

इन निवेशों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत की डेटा सेंटर क्षमता पर पड़ेगा। एआई आधारित सेवाओं को विशाल कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है, और भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के अत्याधुनिक डेटा सेंटर चैटबॉट्स, क्लाउड एप्लिकेशन, एनालिटिक्स और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस को मजबूती देंगे। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को कम लागत में उन्नत एआई टूल्स उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह तकनीकी लोकतंत्रीकरण भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस एआई सुनामी के पीछे भारत की कुछ विशिष्ट ताकतें हैं, जो उसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सस्ता और तेज इंटरनेट, तथा एक अरब से अधिक डिजिटल यूजर्स भारत को अद्वितीय बनाते हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है, जहां इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम और एआई टैलेंट पूल मजबूत है, हालांकि निजी एआई निवेश में यह शीर्ष 5 में नहीं है। आधार, यूपीआई और ओएनडीसी जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणालियों ने भारत को एआई एप्लीकेशन के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला में बदल दिया है। यही कारण है कि वैश्विक कंपनियां यहां केवल बाजार नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नवाचार केंद्र देख रही हैं।

हालांकि, इतनी बड़ी तकनीकी छलांग के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और एल्गोरिदमिक पक्षपात जैसे मुद्दे गंभीर चिंता का विषय हैं। इसके अलावा, ऑटोमेशन के कारण कुछ पारंपरिक नौकरियों के प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को मजबूत डेटा संरक्षण कानून, स्पष्ट रेगुलेटरी ढांचा और नैतिक AI नीति विकसित करनी होगी। साथ ही, घरेलू स्टार्टअप्स और इंडिया एआई मिशन को पर्याप्त संसाधन देकर विदेशी निवेश के साथ संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि

विज़न 2047 की दिशा में केंद्रीय बजट 2026- 27-अमृत काल से विकसित भारत तक की निर्णायक कड़ी - अंतर्राष्ट्रीय समग्र विश्लेषण

बज़ट 2026–27 से आम जनता क़ो सस्ती शिक्षा, सस्ता इलाज, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा और समावेशी आर्थिक भविष्य क़ी उम्मीद सरकार ने आगामी बजट के लिए जनता से 16 जनवरी 2026 तक सुझाव मांगे हैं, जिसमें आम जनता आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय शामिल कर सकते हैं, ताकि बजट बनाने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी हो सके –एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत विजन 2047 के लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर है, जहाँ देश को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और मानवीय मूल्यों से युक्त वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया गया है।इस यात्रा में हर वार्षिक बजट केवल आर्थिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सामाजिक दिशा- सूचक और राष्ट्रीयप्राथमिकताओं का दर्पण होता है। 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत होने वाला केंद्रीय बजट इसी अर्थ में अत्यंत निर्णायक है, बजट 2026-27 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वित्त मंत्रालय के गलियारों में हलचल तेज हो गई है उम्मीद है बज़ट 2026 2027 में भी सरकार अपने विकास के मंत्र पर कायम रहेगी, इसका मतलब है, पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था का इंजन बना रहेगा। हालांकि यह भी उम्मीद है कि वित्तमंत्री का एक हाथ विकास की डोर थामेगा तो दूसरा राजकोषीय घाटे क़ी लगाम कसेगा, क्योंकि यह मध्यम वर्ग, युवाओं, श्रमिकों, किसानों, उद्योगों और स्वास्थ्य- शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए अगले दशक की नींव रख सकता है। बजट 2026 से अपेक्षा है कि वह विकास + कल्याण के भारतीय मॉडल को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूती दे।संभावित 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किए जाने की पूरी संभावना है, हालांकि इस दिन रविवार और गुरु रविदास जयंती होने के कारण तारीख बदलने या इसपर संसदीय समिति द्वारा विचार करने की अटकलें चल रही हैं, लेकिन मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि परंपरा को बनाए रखने के लिए 1 फरवरी की संभावना अधिक है और इस बार शेयर बाजार भी खुल सकता है।सरकार ने आगामी बजट के लिए जनता से 16 जनवरी 2026 तक सुझाव मांगे हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। यह पहल नागरिकों को बजट निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, जिसके लिए जनता से मिले सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।इससे पहले पिछले महीने, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री ने आगामी केंद्रीय बजट 2026 -27 की तैयारियों के तहत नई दिल्ली में पूर्व- बजट परामर्श के कई दौर पूरे किए। इस श्रृंखला की शुरुआत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श से हुई। इसके बाद किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों व बाद के सत्रों में एमएसएमई, पूंजी बाजार, स्टार्टअप, विनिर्माण, बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, और अंत में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों के हितधारकों सहित करीब 13 से अधिक बैठकें की गई है व उनके साथ परामर्श किया गया।

साथियों बात अगर हम विजन 2047 और बदलती राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ इसको समझने की करें तो, विजन 2047 का मूल दर्शन केवल जीडीपी वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव विकास सूचकांक, जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और सतत विकास को केंद्र में रखता है।वैश्विक अनुभव बताता है कि जो देश दीर्घकालिक रूप से सफल हुए , उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को समानांतर रूप से सुदृढ़ किया। बजट 2026 को इसी समग्र दृष्टि से देखा जा रहा है, जहाँ आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुँचे, और मध्यम वर्ग पर बढ़ते दबाव को सख़्ती से कम किया जाए।

साथियों बात अगर हम बजट 2026 में सस्ती शिक्षा, सस्ता इलाज और मध्यम वर्ग के लिए रोजगार पर विशेष ध्यान की आवश्यकता क़ो समझने की करें तो, मध्यम वर्गःभारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़-भारतीय मध्यम वर्ग न केवल उपभोक्ता मांग का प्रमुख स्रोत है, बल्कि कर आधार, उद्यमिता और सामाजिक स्थिरता की रीढ़ भी है। पिछले कुछ वर्षों में महँगाई, शिक्षा शुल्क, स्वास्थ्य खर्च और आवास लागत में वृद्धि ने मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डाला है। बजट 2026 से अपेक्षा है कि वह इस वर्ग को राहत देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों उपाय करे जैसे कर संरचना में सुधार, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और कौशल-आधारित रोजगार सृजन।सस्ती शिक्षाःमानव पूंजी में दीर्घकालिक निवेश विकसित देशों का अनुभव बताता है कि शिक्षा पर किया गया निवेश सबसे अधिक सामाजिक प्रतिफल देता है। भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की लागत तेज़ी से बढ़ी है। बजट 2026 में सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने, डिजिटल और हाइब्रिड लर्निंग को सस्ता बनाने, छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी जैसी पहलों की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिनलैंड, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने सस्ती या लगभग मुफ्त उच्च शिक्षा के माध्यम से नवाचार और उत्पादकता को बढ़ाया, भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ सकता है।सस्ता इलाजःस्वास्थ्य सुरक्षा सेआर्थिक सुरक्षा तकस्वास्थ्य खर्च भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। मध्यम वर्ग अक्सर बीमा कवरेज के बावजूद उच्च आउट- ऑफ- पॉकेट खर्च झेलता है।बजट 2026 में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने, जिला स्तर पर उन्नत अस्पताल, जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य बीमा कवरेज के विस्तार पर जोर

आवश्यक है। सस्ता इलाज केवल मानवीय आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने का साधन भी है।रोजगार सृजनः युवाओं की आकांक्षाओं का उत्तरभारत की जनसांख्यिकीय संरचना युवा है, और रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती। बजट 2026 में श्रम-गहन क्षेत्रों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देकर टिकाऊ रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि कौशल प्रशिक्षण को उद्योग की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने पर ही रोजगार टिकाऊ बनता है।

साथियों बात अगर हम कैंसर जैसी भयंकर बीमारी पर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोडमैप की अनिवार्यता को समझने की करें तो, कैंसरःस्वास्थ्य ही नहीं, सामाजिक-आर्थिक संकट-कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियाँ भारत में तेज़ी से बढ़ रही हैं।यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिरता, कार्यबल की उत्पादकता और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर रोकथाम को प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश माना है।रोकथाम केंद्रित दृष्टिकोणः इलाज से पहले सुरक्षावैश्विक अनुभव बताता है कि कैंसर के लगभग 30-40 प्रतिशत मामलों को जीवनशैली, पर्यावरणीय नियंत्रण और प्रारंभिक जांच से रोका जा सकता है। बजट 2026 में तंबाकू नियंत्रण, प्रदूषण कम करने, पोषण सुधार और नियमित स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के लिए समर्पित फंडिंग आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कैंसर स्क्रीनिंग से जोड़ना एक प्रभावी कदम हो सकता है।सस्ती जांच और इलाजःसमानता का प्रश्न, कैंसर का इलाज अत्यंत महँगा है। बजट में सार्वजनिक- निजी भागीदारी के माध्यम से सस्ती जांच, रेडियोथेरेपी और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का रोडमैप आना चाहिए। जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं को प्रोत्साहन देकर लागत घटाई जा सकती है।अनुसंधान और डेटा-आधारित नीतिअंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैंसर रजिस्ट्रियों और डेटा एनालिटिक्स ने नीति निर्माण को सशक्त बनाया है। भारत में भी राष्ट्रीय कैंसर डेटा नेटवर्क और स्वदेशी अनुसंधान को बजट समर्थन मिलना चाहिए, ताकि भारतीय संदर्भ में प्रभावी समाधान विकसित हों।

साथियों बात अगर हम आयकर विभाग की 13 से अधिक वर्गों से प्री-बजट कंसल्टेशनः सुझावों का विस्तृत विश्लेषण करने की करें तो, समावेशी नीति निर्माण की पहल-आयकर विभाग द्वारा 13 से अधिक विभिन्न वर्गों उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, वेतनभोगी, वरिष्ठ नागरिक, कृषि-आधारित उद्यम, वित्तीय क्षेत्र, कर पेशेवर, निर्यातक, सामाजिक क्षेत्र और शिक्षाविदों, से प्री-बजट परामर्श एक लोकतांत्रिक और समावेशी पहल है। इसका उद्देश्य जमीनी अनुभवों को नीति में शामिल करना है।उद्योग और एमएसएमई के सुझाव-उद्योग जगत ने कर सरलीकरण, अनुपालन लागत में कमी और निवेश प्रोत्साहन की मांग की। एमएसएमई ने आसान क्रेडिट, कर विवादों के शीघ्र निपटान और डिजिटलअनुपालन में सहायता पर जोर दिया। स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र स्टार्टअप्स ने कर प्रोत्साहन की निरंतरता, एंजेल टैक्स जैसी जटिलताओं से राहत और अनुसंधान पर टैक्स क्रेडिट का सुझाव दिया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए यह महत्वपूर्ण माना गया।वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक-वेतनभोगी वर्ग ने आयकर स्लैब में राहत, मानक कटौती बढ़ाने और महँगाई के अनुरूप कर ढांचे को समायोजित करने की मांग की। वरिष्ठ नागरिकों ने स्वास्थ्य खर्च पर अतिरिक्त कर छूट और सरल रिटर्न प्रक्रिया का सुझाव दिया।सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र तथा सामाजिक संगठनों और शिक्षाविदों ने शिक्षा -स्वास्थ्य पर कर प्रोत्साहन, परोपकारी दान को बढ़ावा और मानव विकास को कर नीति से जोड़ने की बात कही।

साथियों बात अगर हम 1 फरवरी 2026 के बजट में संभावित प्रस्तावः एक अग्रिम दृष्टि इसको समझने की करें तो, कर सुधार और मध्यम वर्ग राहत-संभावना है कि बजट 2026 में आयकर स्लैब में युक्तिसंगत बदलाव, मानक कटौती में वृद्धि और अनुपालन को और सरल किया जाएगा।अप्रत्यक्ष करों में स्थिरता बनाए रखते हुए उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहन मिल सकता है।शिक्षा और कौशल पर बढ़ा आवंटन-डिजिटल शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और कौशल भारत मिशन के विस्तार के लिए अतिरिक्त संसाधन संभावित हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा मिल सकता है।स्वास्थ्य और कैंसर रोडमैप-सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, कैंसर रोकथाम और उपचार के लिए राष्ट्रीय मिशन, और हेल्थ-टेक नवाचार को समर्थन संभावित प्रस्तावों में शामिल हो सकते हैं।रोजगार और ग्रीन ग्रोथ ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जलवायु अनुकूल कृषि और शहरी अवसंरचना में निवेश से नए रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं। यह भारत को वैश्विक जलवायु नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि संभावित बजट 2026-27 आर्थिक दस्तावेज़ से सामाजिक अनुबंध तक, बजट 2026-27 केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत और उसके नागरिकों के बीच एक नए सामाजिक अनुबंध की तरह देखा जा रहा है।सस्ती शिक्षा, सस्ता इलाज, रोजगार सृजन, कैंसर जैसी बीमारियों पर रोकथाम और समावेशी कर नीति, ये सभी मिलकर विजन 2047 को साकार करने की आधारशिला रख सकते हैं। यदि बजट 2026-27 मानवीय दृष्टि, आर्थिक विवेक और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का संतुलन साध पाया, तो यह भारत को न केवल आर्थिक महाशक्ति, बल्कि एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज के रूप में भी स्थापित करेगा।

बिनोद बिहारी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , राज्यपाल संतोष गंगवार बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई. यह कार्यक्रम न्यू टाउन हॉल में हुआ. राज्यपाल ने 164 पी एच डी और गोल्ड मेडलिस्ट छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की.

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि यह दिन छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की है. उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री लेने का मौका नहीं है, बल्कि जीवन में नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की एक औपचारिक शुरुआत

राज्यपाल ने कहा कि आज का दौर सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है. खोज, इनोवेशन और रिसर्च के लिए नए अवसरों की लगातार तलाश करने की जरूरत है. इससे छात्रों और देश को एक नई दिशा मिलेगी. शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए. छात्रों को हमेशा अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर करना चाहिए.

उन्होंने छात्रों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया. अगर हर पढ़ा-लिखा युवा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक बच्चे के भविष्य को संवारने का संकल्प ले, तो निरक्षरता, गरीबी और असमानता की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षा को समावेशी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटी सत्र नियमित हों और प्रक्रियाएं ठीक से हों. खाली पदों को भरने के प्रयास जारी हैं. कुछ जगहों पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन यह अगले महीने तक पूरी हो जाएगी. आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में समस्याएं कम से कम होंगी.उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी है. कम छात्र एडमिशन ले रहे हैं, और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. पास हुए छात्रों ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और बेहतर भविष्य के लिए टिप्स भी दिए।

मिर्ज़ा ग़ालिब गालिब, शायरी का बादशाह

डॉ.मुश्ताक़ अहमद

महान शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान ग़ालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। मुग़ल बादशाहों के ज़माने में पैदा हुए गालिब ने उर्दू शायरी को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया। उनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान था, और 'ग़ालिब' उनका तख़ल्लुस था, जो उनकी शायरी में गूँजता है। ग़ालिब की शायरी में इश्क़, दर्द, फ़लसफ़ा और ज़िंदगी की हक़ीक़तें बख़ूबी बयान होती हैं। उनका मशहूर शेर है,

"हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले,

बहुत निकले मिरे अरमान लेकिन फ़िर भी कम निकले।₹यह शेर उनकी ग़ज़ल की रूह है, जो इंसान के अनगिनत तमन्नाओं को बयान करता है। ग़ालिब ने दिल्ली के दरबार में नवाबों और बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ रहकर शायरी की महफ़िलें सजाईं। 1857 की क्रांति ने उनकी ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिया, लेकिन उनकी क़लम न रुकी।उनकी दुआएं और शायरी आज भी दिलों को छूती हैं। ग़ालिब ने फ़ारसी और उर्दू दोनों में क़सीदे, मसनवी और ग़ज़लें लिखीं। उनकी किताब 'दीवान-ए-गालिब' उर्दू अदब की अमूल्य निधि है। ग़ालिब की शायरी में हास्य, विर्भाव और गहन चिंतन का अनोखा संगम है।आज 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाते हुए हम उनकी याद ताज़ा करते हैं। ग़ालिब साहब की शायरी हमें सिखाती है कि दर्द में भी हुस्न छिपा है। उनकी ये पंक्तियाँ अमर हैं,

इश्क़ ने 'ग़ालिब' निकम्मा कर दिया,
वरना हम भी आदमी थे काम के।₹ग़ालिब की विरासत शायरी को अमर बनाए रखेगी।

काल चक्र के नये पड़ाव के स्वागत की बेला

डा. विनोद बब्बर

समय की सत्ता अखंड और अनंत है। वही सम्पूर्ण सृष्टि का, सम्पूर्ण ब्रह्मांड का सर्जक है, नियामक भी है। वह न कभी शुरू हुआ, न कभी खत्म होगा। वह न चलता है, न रुकता है, न जाता है, न आता है। वही सर्जक है, पालनहार है और उसी के भीतर सब कुछ है, ।उसकी अपनी लय है।असम्भव को सम्भव करने की शक्ति है। पर मनुष्य की दृष्टि सीमित है। कालचक्र के प्रवाह को समझने के लिये मनुष्य समय की हदबंदी में बांटकर देखने में सुविधा अनुभव करता है। उसने समय को भूत, वर्तमान और भविष्य में बांटा लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर उसका और विभाजन कर छोटी इकाइयां बनाई। पल-पल से शुरु हुई कालचक्र की यह यात्रा घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, दशक, शती और इसी तरह युग-युगाब्द की कल्पना तक जा पहुंची। वर्ष मनुष्य के जीवन को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मानक मान लिया गया। इसी अर्थ में हर नया वर्ष किसी भी समाज, राष्ट्र अथवा विश्व को अपनी पिछले वर्ष की कामयाबियों, नाकामयाबियों के बारे में मूल्यांकन और भविष्य के नये लक्ष्य निश्चित करने का मौका देता है। सम्भवतः इसी नजरिये ने आदमी को नववर्ष मनाने की प्रेरणा दी होगी।

यह परम्परा प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। दुनिया भर के तमाम समाजों, जातियों और समुदायों, सम्प्रदायों में अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग तिथियों, महीनों में नववर्ष मनाने की परम्परा है। सांस्कृतिक दृष्टि से पृथक-पृथक समूहों में नववर्ष के महत्व को लेकर अनेक मिथकीय कथायें प्रचलित हैं। सदियों से चले आ रहे कुछ विश्वास भी हैं और कुछ अन्धविश्वास भी। यद्यपि दुनिया के एक हिस्से में नये साल की शुरुआत एक जनवरी से मानी जाती है लेकिन इसके बावजूद अनेक देशों और जातीय अस्मिताओं वाले समाजों में आज भी वर्ष के अलग-अलग महीनों में नववर्ष मनाने की परम्परा है। स्थानीय किंतु प्राचीन परम्पराओं और विश्वासों में सदियों से बँधे होने के कारण वे ऐसा करते हैं। ईरानी और बहावी नववर्ष 21 मार्च को, नेपाली, सिंहल और थाई 14 अप्रैल को, पारसी 23 अप्रैल को, मोरक्कन 3 अक्टूबर को, वियतनामी 17 जनवरी को, केल्टिक 21 जनवरी को और मिस्र में यह 7 जनवरी को मनाया जाता है। इस्लामी देश इस्लामी कैलेंडर के अनुसार अपना नया साल मुहर्रम माह की पहली तिथि को मनाते हैं। इसी तरह भारतीय नववर्ष चैत्र माह के प्रथम दिन होता है। पारम्परिक भारतीय कैलेंडर विक्रमी सम्वत के अनुसार चलता है।

भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्ष का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल से होता है। यह सृष्टि के आरम्भ का दिन भी है। यह वैज्ञानिक तथा शास्त्रशुद्ध गणना है। ठिठुरती ठंड मे पड़ने वाले ईसाई नववर्ष पहली जनवरी से भारतवंशियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतवर्ष वह पावन भूमि है जिसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अपने ज्ञान से आलोकित किया है। वह केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के कल्याण का पोषक है जो प्रकृति और विज्ञान का ऐसा विलक्षण उदाहरण है। सत्य तो यह है कि भारतीय नववर्ष उसी नवीनता के साथ देखा जाता है. नए अन्न किसानों के घर में पहुंच जाते हैं, वृक्ष में नए पल्लव यहाँ तक कि पशु-पक्षी भी अपना स्वरूप नए प्रकार से परिवर्तित कर लेते हैं. होलिका दहन से बीतेहुए वर्ष को विदा कहकर नवीन संकल्प के साथ वाणिज्य व विकास की योजनायें प्रारंभ हो जाती है।

हमारे महापुरुषों का भी कथन है कि निज गौरव को खोना आत्मघाती होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 'यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है, अपने अन्तर्मन में राष्ट्र भक्ति के बीज को पल्लवित करना है तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। गुलाम बनाए रखने वाले प्रतीकों को महिमा मंडित करने से आत्म सम्मान नष्ट होता है।' इसी प्रकार महात्मा गांधी ने 1944 में अपनी पत्रिका में लिखा था, 'स्वराज का अर्थ है स्वसंस्कृति, स्वधर्म एवं स्वपरम्पराओं का हृदय से निर्वहन करना। पराया धन और परायी परम्परा को अपनाने वाला न तो ईमानदार कहलाता है और नहीं आस्थावान।' जहां तक भारत का प्रश्न है, 'अनेकता में एकता' का मंत्र लिये हमारे देश में नववर्ष दिवस भी अनेक हैं जो अपनी -अपनी समृद्ध परम्पराओं से जुड़े हुए हैं। असम में बीहू, केरल और तमिलनाडु में विशु के नाम से, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से और पंजाब में बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह नयी फसल के त्योहार के रूप में आता है। गुजरात और पश्चिम बंगाल दीवाली को नया साल मनाते हैं। बौद्ध और जैन मतावलम्बी क्रमशः बुद्ध पूर्णिमा और भगवान महावीर की मोक्ष तिथि को मनाते हैं। विडम्बना यह है कि आज तक अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक अंग्रेजी नववर्ष का कोई औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सका है परंतु हम भेड़चाल का शिकार होकर 'हैप्पी न्यू ईयर' की धुन पर नाचने लगे हैं।

आज जब ठिठुरन, जकड़न, धुंध, अंधेरा, आलस्य अपने चरम पर है तो क्यों न हम भी इस कर्मकांड को पूरा करने की रस्म अदायगी करते हुए वर्ष 2025 का समीक्षा करें। यह वर्ष चुनौतियों पर विजय का रहा। एक ओर अमेरिकी टैरिफ दबाव तो दूसरी ओर आतंकवाद का दंश झेलते हुए हमने दोनों का धैर्य और साहस से सामना करते हुए विश्व को अचंभित किया। इस वर्ष भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल और राष्ट्रीय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गईं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 200 से अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिसमें पहला ऑन-ऑर्बिट डॉकिंग प्रयोग (SPADEX) और आदित्य-L1 मिशन से डेटा जारी करना शामिल है। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने।

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हमारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) $4 ट्रिलियन तक पहुंचा। हमारी डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI के बढ़ते कदम यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरीशस, फ्रांस और श्रीलंका तक पहुंचे। अर्थव्यवस्था के उठान का परिणाम है कि इस वर्ष आयकर छूट सीमा आशा से बढ़कर 12 लाख की गई।

आतंकवाद का जवाब देते हुए हमारी सेना ने कुछ मिनटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाक की गुहार पर भारत ने युद्ध विराम स्वीकार किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से लेने को आतुर हुए लेकिन भारत में दृढ़ता से अमेरिकी हस्तक्षेप को दृढ़ता से अस्वीकार किया। भारत में अनेक अति आधुनिक हथियारों का न केवल सफल परीक्षण किया अपितु उत्पादन को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। आज विश्व में भारतीय मिसाइलों तथा अन्य हथियारों की मांग बढ़ी है। संक्षेप में कहे तो विश्व मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है इसीलिए विश्व शांति के प्रयासों में भारत की भूमिका बढ़ी है।

36 से घटकर अब 3 जिलों तक सीमित हो चुका नक्सलवाद अंतिम सांस से गिन रहा है तो दशकों अशांत रहा कश्मीर अपेक्षाकृत शांति से लोकतंत्र की राह पर बढ़ रहा है। पूरे देश में आधुनिकतम सड़कों, रेल मार्गों और हवाई अड्डों का विस्तार पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है लेकिन विपक्ष किसी उपलब्धि को मानने को तैयार नहीं । आशा है कालचक्र के नए पड़ाव अर्थात वर्ष 2026 में किसान, श्रमिक की खुशहाली और छात्रों के प्रतिभा विस्तार से पूरा भारत गौरवांवित अनुभव करेगा । देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, संचार, आवास की विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होगी।

इतिहास के पन्नों में सिमट रहे वर्ष 2025 में विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शताब्दी पूर्ण की। वर्ष के अंतिम चरण में जब भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए अनेक नामों की अटकलें लगाई जा रही थी अचानक लो प्रोफाइल युवा श्री नीतिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व मिला तो सौ वर्ष से अधिक की हो चुकी कांग्रेस का नेतृत्व लगातार असफल हो रहे राहुल से अघोषित रूप से प्रियंका की ओर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्ष-विपक्ष के अनावश्यक टकराव के कारण संसद का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ।

नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार :लोकतंत्र की जीत का समय

-सुनील कुमार महला

हाल ही में ओडिशा के कंधमाल में मुठभेड़ के दौरान 6 और नक्सली मारे गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नक्सली कमांडर व एक करोड़ का इनामी गणेश उइके,जो सैंट्रल कमेटी मेंबर था, भी इस मुठभेड़ में मारा गया। वास्तव में, गणेश उइके को कंधमाल जिले में खास खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मारा गया है और इस संबंध में स्वयं हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सेंट्रल कमेटी का सदस्य उइके तीन दशक तक छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना के साथ ही ओडिशा में सक्रिय रहा था तथा उस पर 1.10 करोड़ का बड़ा इनाम था। कहना ग़लत नहीं होगा कि उसकी मौत नक्सलियों के खिलाफ अभियान में एक बहुत ही बड़ी सफलता है।

माओवादी हिंसक तंत्र की कमर टूटी:-

वास्तव में, सच तो यह है कि हाल में एक और खूंखार व इनामी माओवादी नेता की मौत के साथ ही ओडिशा में माओवादी हिंसक तंत्र की कमर टूट गई है। पाठकों को बताता चलूं कि कंधमाल जिले के चाकपाड़ थाना क्षेत्र में 25 दिसंबर 2025 गुरुवार तड़के सुरक्षा बलों के साथ हुई गोलीबारी में गणेश उइके के अलावा एक महिला कैडर सहित तीन नक्सली को ढेर कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उइके की गिनती बर्बर नक्सलियों में होती थी और सरकार द्वारा बार-बार चेतावनी व सलाह के बावजूद उसने अराजकता,हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा था। अगर वह समर्पण कर देता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मारा गया। हाल के समय में जिस नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वह अत्यंत खतरनाक था और देश की सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ था। ऐसे व्यक्ति का अंत होना संविधान की दृष्टि से भी उचित है, क्योंकि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे और नागरिकों के जीवन व अधिकारों की रक्षा करे।साथ ही, समाज के नजरिए से भी यह कार्रवाई सही ठहराई जा रही है, क्योंकि इससे हिंसा, आतंक और भय के माहौल पर रोक लगती है तथा शांति और स्थिरता स्थापित करने में मदद मिलती है।सरल शब्दों में कहें तो ऐसे खतरनाक नक्सली का मारा जाना कानून और सामाजिक हित दोनों के लिहाज से सही है।

नक्सलवाद से निपटने हेतु सरकार की बहुआयामी नीतियां:-

यहां पाठकों को बताता चलूं कि सरकार नक्सल समस्या के समाधान के लिए केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने हेतु बहुआयामी रणनीति अपना रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न नीतियां लागू की हैं, जिनके तहत हथियार डालने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार, विभिन्न कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य

जैसी अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कई मामलों में कानूनी सहायता और लंबित मामलों में राहत तक भी दी जाती है, ताकि वे बिना भय के समाज की मुख्यधारा में लौट सकें और सामान्य व अच्छा जीवन जी सकें। इसके साथ ही प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों द्वारा संवाद, जनअपील और परिवारजनों के माध्यम से नक्सलियों तक विश्वास का संदेश पहुंचाया जाता है। आज नक्सल प्रभावित इलाकों में विभिन्न बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, स्कूल(इंफ्रास्ट्रक्चर) अस्पताल और रोजगार योजनाओं के जरिए विकास को गति दी जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों की नाराजगी कम हो और उग्रवाद की जमीन कमजोर पड़े। 'सुरक्षा, विकास और विश्वास' की नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास किया जाता है। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम यह है कि हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में नक्सल हिंसा में अभूतपूर्व रूप से कमी आई है और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण किया है।

सिमटी नक्सल संगठन की संख्या:-

बहरहाल, मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीते दो दिनों में छह नक्सली वहां ढेर हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंदूर मंडल के पुल्लेमाला गांव का रहने वाला गणेश उइके 7 नामों पक्का हनुमंत, रूपा, राजेश तिवारी, चमरू दादा, गजराला रवि और सोमरू के नाम से भी जाना जाता था। कितनी बड़ी बात है कि वह 69 साल की उम्र में भी लाल आतंक(नक्सलवाद) का झंडा उठाए हुए था। यहां पर यह भी गौरतलब है कि साल 2025 में नक्सल संगठन में 22 सेंट्रल कमेटी मेंबर थे तथा साल के अंत तक यह संख्या 3 पर आकर सिमट चुकी है। उइके के मारे जाने के बाद अब संगठन (नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व) बिखर चुका है। मई 2025 में अबूझमाड़ में सेंट्रल कमेटी के महासचिव बसव राजू के मारे जाने के बाद फोर्स को लगातार सफलता मिलती रही तथा बड़ी संख्या में सेंट्रल कमेटी के सदस्य इस दौरान मारे गए। यहां पर यह भी ध्यान देने की बात है, अभी 23 दिसंबर 2025 को ही 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन 69 साल की उम्र हो जाने के बावजूद उइके बंदूक रखने को तैयार नहीं हुआ और यही वजह है कि वह अपने अंजाम को प्राप्त हुआ।

केन्द्र सरकार की माओवाद के संबंध में स्पष्ट नीतियां:-

वास्तव में केंद्र सरकार की नीति और रणनीति माओवादी हिंसा को लेकर बहुत स्पष्ट है। दरअसल,हमारे देश में माओवादी (या नक्सली) हिंसा के खिलाफ सरकार की नीतियाँ बहुमुखी रणनीति, जैसा कि ऊपर भी इस आलेख में चर्चा कर चुका हूं, पर आधारित हैं, जिसमें सुरक्षा-कदम, विकास-कार्य, आत्मसमर्पण-और-पुनर्वास कार्यक्रम और सामाजिक सहभागिता शामिल हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि पिछले कुछ समय से सरकार ने माओवादी हिंसा के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाई है, जिसका लक्ष्य माओवादी उपस्थित क्षेत्रों में हिंसा को समाप्त करना है।इस नीति के तहत आज शीर्ष माओवादी कमांडरों और कैडरों को निष्क्रिय/हत्या/गिरफ्तार किया जा रहा है, माओवादी संपत्ति और वित्तीय सहायता को जब्त किया जा रहा है तथा सुरक्षा बलों का समन्वित अभियान चलाकर हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप माओवादी हिंसा में कमी दर्ज की गई है और प्रभावित ज़िलों की संख्या लगातार घट रही है।माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में विकास-कार्यों(जैसे कि सड़क, पुल, मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार)पर जोर दिया गया है ताकि अधारभूत सेवाओं और सरकारी उपस्थिति को मजबूत किया जा सके। आज सरकार और प्रभावित राज्य सरकारें मिलकर माओवादी कैडरों को हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए उन्हें आत्मसमर्पण-और-पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इतना ही नहीं,सरकार ने कुछ क्षेत्रों में समुदाय-पुलिस सहयोग, स्वास्थ्य शिविर, खेल और कौशल कार्यशालाओं जैसे कदम उठाएं हैं ताकि स्थानीय जनता का विश्वास जीता जा सके और हिंसा के समर्थन को कम किया जा सके। सरकार द्वारा आज माओवादी संगठन बैन्ड/अवैध घोषित किए गए हैं और उनके सहयोग/प्रचार को दंडनीय बनाया गया है।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) जैसे संस्थानों को वित्तीय नेटवर्क व उग्र गतिविधियों की निगरानी के लिए सुदृढ़ किया गया है। वास्तव में सरकार का दीर्घकालिक माओवादी हिंसा को न केवल काबू में करना है, बल्कि इसे मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त करना है। अंत में यही कहूंगा कि बीतते वर्ष में यानी कि वर्ष 2025 में माओवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों का एक शीर्ष नेता बसवराजू मई-2025 में मारा गया, उसके बाद हिडमा और अब उइके के मारे जाने से नक्सली संगठन की रीढ़ लगभग टूट चुकी है। जो बचे हुए नेता/कैडर हैं, उनके लिए भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जैसा कि केंद्र सरकार ने यह साफ संकल्प लें लिया है कि अगले साल यानी कि वर्ष 2026 के मार्च तक माओवाद को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। कहना ग़लत नहीं होगा कि सरकार की इसी दृढ़ता(दृढ़ संकल्प और निश्चय) के कारण ही नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और सक्रियता पहले की तुलना में काफी हद तक बढ़ी है। ओडिशा में चलाए गए अभियान से यह साफ दिखता है कि सरकार किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। एसओजी, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की कई टीमें जंगलों में तैनात हैं, ताकि जवानों को कम से कम नुकसान हो और माओवादियों को कड़े से कड़ा जवाब दिया जा सके। ऐसे में बचे हुए माओवादियों के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि वे हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करें, क्यों कि समाज सुधार और संघर्ष के और भी शांतिपूर्ण रास्ते हो सकते हैं। पिछले चार-पांच दशकों की हिंसा से उन्हें और समाज को आखिर क्या मिला, इस पर भी विचार करना चाहिए।सच तो यह है कि बिना हिंसा पर काबू पाए विकास संभव नहीं है।

आज 126 जिलों से रह गये मात्र 11 :-

यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि 2014 में जहां 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज उनकी संख्या घटकर केवल 11 रह गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले 36 से घटकर सिर्फ तीन बचे हैं। वास्तव में, आज देश से नक्सली हिंसा का डर काफी हद तक कम हुआ है। बीते साल में 317 से ज्यादा नक्सली मारे गए, 800 से अधिक गिरफ्तार हुए और करीब 2,000 ने आत्मसमर्पण किया। यह सफलता दिखाती है कि माओवाद के अंत की दिशा में देश एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। निष्कर्ष के तौर पर यह बात कही जा सकती है कि नक्सलवाद एक ऐसी हिंसक और विध्वंसक विचारधारा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और विकास की प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाती है। यह न केवल निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों की जान लेता है, बल्कि जिन इलाकों में इसका प्रभाव रहता है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी बाधा बनता है।जब तक नक्सलवाद जैसे सशस्त्र आंदोलन मौजूद रहते हैं, तब तक देश और समाज में न तो शांति स्थापित हो सकती है और न ही समावेशी विकास संभव है। इसलिए इसे केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और विकास से जुड़ा मुद्दा मानते हुए समाप्त करना आवश्यक है।हालाँकि, इसका समाधान सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद की जड़ों में मौजूद गरीबी, पिछड़ापन, प्रशासनिक उपेक्षा और असंतोष को भी दूर करना उतना ही जरूरी है। सख्त कार्रवाई के साथ संवाद, विकास और विश्वास-इन तीनों के संतुलन से ही देश स्थायी रूप से प्रगति और उन्नयन के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है।

शीर्षक - दृढ़ संकल्प शक्ति (बाल कविता)

बच्चों दृढ़ निश्चय का अनूठा बल तुम जानो,
इस आत्मिक अनंत शक्ति को तुम पहचानो,
उच्च शिक्षा व शुभ संस्कारों को शस्त्र बनाओ,
अपनी बुद्धिमत्ता शक्ति को नित ही बढ़ाओ ।

अपने इंद्रधनुषी सपनों को करो पूर्णत: साकार,
मिटा दो राहों के कंटक बना हौसले को हथियार,
दृढ़ संकल्प शक्ति को बनाकर श्रम का आधार,
जीवन को तुम दो अपने नया आकाशीय विस्तार ।

दृढ़ निश्चय संकल्प ने असंभव विजय भी दिलाई,
आशाओं के ऑगन में स्वयं अपनी मंजिल पाई,
साहस ने मुश्किलों को रौंद भीतर उम्मीद जगाई,
विश्वास व ₹आनंद₹ की लहर आँखों में दी दिखाई ।

दृढ़ निश्चय ने खुशियों को जीवन का श्रृंगार बनाया,
दृढ़ निश्चय ने सदियों से नया एक इतिहास रचाया,
इच्छित पुरस्कार को मेहनत के मोतियों से सजाया,
आत्मबल ने हर कठिनाई को फिर कमजोर बनाया ।

- मोनिका डागा ₹आनंद₹, चेन्नई, तमिलनाडु
आपके स्नेह और प्यार का धन्यवाद !
रचना (स्वरचित व सर्वाधिकार सुरक्षित)

12वीं बायोलॉजी के बाद कैरियर

डॉ. विजय गर्ग

तमिल परंपरा पर आधारित सिद्धा चिकित्सा पंचभूत सिद्धांत पर कार्य करती है। लाभ : त्वचा, अस्थि, और दीर्घकालिक दर्द रोगों में कारगर। कोर्स अवधि : 5 .5 वर्ष (4 .5 वर्ष अध्ययन + 1 वर्ष इंटर्नशिप)। न्यूनतम योग्यता :12वीं (पीसीबी विषयों) में 50 फीसदी अंक से उत्तीर्ण। प्रवेश नीट आधारित (अधिकतर संस्थान तमिलनाडु में)।

एलोपैथी व आयुर्वेद के अलावा देश में चिकित्सा की कई पूरक पद्धतियां कैरियर के बेहतर विकल्प प्रदान करती हैं। ये सभी प्राकृतिक, सुरक्षित और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देने पर केंद्रित हैं। आज दुनिया भर में आयुष प्रणालियों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

भारत की पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा प्रणालियां- आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा-रिगपा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और योग- न केवल स्वास्थ्य संरक्षण का मजबूत आधार हैं, बल्कि आज युवाओं के लिए कैरियर के विशाल अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। इनका साझा लक्ष्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित कर, व्यक्ति को एक स्वस्थ्य एवं प्रसन्नचित्त जीवन प्रदान करना है।

बीयूएमएस (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी)

यूनानी चिकित्सा प्रणाली शरीर के चार रसों (खून, बलगम, सफ़रा, सऊदा) के संतुलन से स्वास्थ्य निर्धारित करती है। लाभ : जड़ी-बूटी आधारित उपचार, क्रोनिक बीमारियों में प्रभावी। कोर्स की कुल अवधि 5.5 वर्ष है, इसमें 4.5 वर्ष की अकादमिक पढ़ाई + 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप। न्यूनतम योग्यता12वीं कक्षा (पीसीबी–भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान) न्यूनतम 50 फीसदी अंक (अनुसूचित जाति , जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट) के साथ उत्तीर्ण हो। प्रवेश 'नीट' स्कोर के आधार पर। इंटर्नशिप : विभिन्न यूनानी अस्पतालों, औषधनिर्माण यूनिट, ओपीडी में 1 वर्ष की इंटर्नशिप। जॉब अवसरः यूनानी डॉक्टर/हकीम, यूनानी अस्पताल, डिस्पेंसरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनानी फार्मेसी व औषधि उद्योग, निजी क्लिनिक स्थापना का अवसर, सरकारी आयुष सेवाएं यानी आयुष मेडिकल ऑफिसर।

बीएसएमएस (बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी)

तमिल परंपरा पर आधारित सिद्धा चिकित्सा पंचभूत सिद्धांत पर कार्य करती है। लाभ : त्वचा, अस्थि, और दीर्घकालिक दर्द रोगों में कारगर। कोर्स अवधि : 5.5 वर्ष (4.5 वर्ष अध्ययन + 1 वर्ष इंटर्नशिप)। न्यूनतम योग्यता:12वीं (पीसीबी विषयों) में 50 फीसदी अंक से उत्तीर्ण। प्रवेश नीट आधारित (अधिकतर संस्थान तमिलनाडु में)। इंटर्नशिप : सिद्धा अस्पताल, पंचकर्म/वरमा क्लिनिक आदि में 1 वर्ष। अवसर : सिद्धा चिकित्सक, सिद्धा अस्पताल, रिसर्च केंद्र, टीचिंग संस्थान, औषध निर्माण—हर्बल/मिनरल दवाइयां, निजी क्लिनिक व वेलनेस सेंटर में जॉब।

बीएसआरएमएस (बैचलर इन सोवा-रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी)

तिब्बती चिकित्सा प्रणाली मन-ऊर्जा-शरीर को केंद्र में रखती है। लाभ : मानसिक स्वास्थ्य, क्रोनिक रोगों, और ध्यान-आधारित उपचार में उपयोगी। कोर्स अवधिः 5.5 वर्ष (4.5 वर्ष अध्ययन + 1 वर्ष इंटर्नशिप), न्यूनतम योग्यता : 12वीं (पीसीबी) 50 फीसदी अंक। कुछ संस्थान अपनी प्रवेश परीक्षा लेते हैं मुख्यतः लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल आदि क्षेत्रों में इसके संस्थान हैं। इंटर्नशिप : तिब्बती चिकित्सा अस्पतालों व अनुसंधान केन्द्रों में 1 वर्ष। जॉब अवसर : सोवा-रिगपा चिकित्सक, तिब्बती अस्पताल, औषधि यूनिट, रिसर्च व डॉक्टरी प्रैक्टिस, सरकारी आयुष सेवाओं में अवसर।

बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी)

'सिमिलर क्योर्स सिमिलर' सिद्धांत पर आधारित यह पद्धति अत्यंत सूक्ष्म खुराकों से उपचार करती है। लाभः बिना दुष्प्रभाव के, बच्चों और वृद्धों के लिए सुरक्षित। कोर्स अवधि, 5.5 वर्ष (4.5 वर्ष पढ़ाई + 1 वर्ष इंटर्नशिप) है। न्यूनतम योग्यता12वीं (पीसीबी विषयों के साथ) 50 फीसदी अंक से उत्तीर्ण की हो। प्रवेश नीट स्कोर आधारित। इंटर्नशिप : होम्योपैथिक अस्पतालों, डिपार्टमेंट्स और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 वर्ष। जॉब अवसर :होम्योपैथी डॉक्टर, सरकारी आयुष विभाग, होम्योपैथिक अस्पताल, निजी क्लिनिक, वेलनेस सेंटर, फार्मास्युटिकल उद्योग व रिसर्च में।

बीएनवाईएस (बैचलर इन नेचरोपैथी एंड योगा)

नेचुरोपैथी प्रकृति की पंचतत्वीय शक्तियों—जल, वायु, मिट्टी, सूर्य और आहार—द्वारा उपचार करती है। लाभः दवा-रहित उपचार, जीवनशैली सुधार, मोटापा, मधुमेह और तनाव नियंत्रण में प्रभावी। कोर्स अवधि 5.5 वर्ष (4.5 वर्ष पढ़ाई + 1 वर्ष इंटर्नशिप) है। न्यूनतम योग्यता :12वीं (पी सी बी) 50 फीसदी अंक के साथ उत्तीर्ण हो। कुछ संस्थान नीट स्कोर स्वीकार करते हैं, कई अलग प्रवेश परीक्षा/मेरिट सूची तैयार करते हैं। इंटर्नशिप, नेचुरोपैथी अस्पताल, योग थेरेपी विभाग, आहार विज्ञान केंद्र में 1 वर्ष की रहती है। जॉब अवसर : नेचरोपैथी डॉक्टर, योग थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथी विशेषज्ञ, वेलनेस क्लिनिक, हेल्थ रिसॉर्ट, कॉर्पोरेट योग ट्रेनर, सरकारी आयुष सेवाएं व शिक्षण क्षेत्र।

योग एवं योग-चिकित्सा (डिप्लोमा/स्नातक/ थेरेपी कोर्स)

योग केवल आसन ही नहीं, बल्कि प्राणायाम, ध्यान और जीवनशैली का सम्मिलित स्वरूप है। लाभः मानसिक शांति, तनाव-नियंत्रण, हार्मोनल संतुलन, क्रोनिक रोगों में सहायक। अवधि डिप्लोमा : 1 वर्ष, स्नातक डिग्री (योग): 3 वर्ष, स्नातकोत्तर (योग): 2 वर्ष, पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी : 1 वर्ष है। न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा के लिए 12वीं उत्तीर्ण, स्नातक कोर्स के लिए 12वीं (किसी भी स्ट्रीम), स्नातकोत्तर हेतु किसी भी विषय में ग्रेजुएशन। जॉब अवसर : योग प्रशिक्षक, योग थेरेपिस्ट, अस्पतालों, स्पोर्ट्स संस्थानों, वेलनेस सेंटर, अंतरराष्ट्रीय योग शिक्षक, कॉर्पोरेट/स्कूलों में योग ट्रेनर, निजी योग स्टूडियो स्थापित करने का अवसर उपलब्ध हैं। आयुष मंत्रालय/एनआईएसएम जैसे संस्थानों में भी अवसर उपलब्ध रहते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट

जीवन के स्रोत

डॉ विजय गर्ग

हम सब प्रकृति के हिस्से हैं, जिनमें कुछ जीव धरती पर, कुछ जल में, कुछ पेड़ों पर तो कुछ अलग-अलग जगहों पर रहते हैं। हम कभी-कभी खुद को ही सबसे अधिक महत्त्व देने लगते हैं। हमारे आसपास कितने ही जीव-जंतु ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में कुत्तों को मार डालने की खबर आई। उसके बाद सोशल मीडिया पर कुत्तों के काटने की खबरों की बाढ़ आ गई। बहुत सारे लोग उनके पक्ष में तो बहुत सारे उसके विपक्ष में आ गए और मामला अदालत तक पहुंच गया। हमें किसी जीव से नुकसान होने के साथ-साथ उससे होने वाले नुकसान के कारणों पर काम करना चाहिए। किसी को उसकी जगह से निष्कासित या विस्थापित करना उसके अस्तित्व को खतरे में डालना है।

लावारिस जीव-जंतु भी जिस जगह पर रहते हैं, वे उस जगह के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वे वहां रहना चाहते हैं। उन्हें वहां से हटाकर नए अपरिचित माहौल में रखना उनके लिए कष्टप्रद होता है। उनके लिए आवश्यक विकल्प, सुविधाएं और आवास की व्यवस्था या जिस तरह वे रह रहे थे, वह व्यवस्था न छीनकर उसे सुगम बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। बहुत सारे लोग कुत्तों को पालते हैं, लेकिन जिन कुत्तों को लोग नहीं पालते, वे लावारिस सड़कों पर घूमते रहते हैं और भोजन तथा आवास के लिए दर-दर भटकते रहते हैं।

लगभग बीस-पच्चीस वर्ष पहले तक कस्बों और गांवों में बहुत से घरों से पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने का चलन था। लोग जो कूड़ा फेंक देते थे, उसमें बचा हुआ भोजन भी होता था, जिसे लावारिस पशु खा लेते थे।

मजबूरी में पीने का पानी नालियों से पी लेते थे।

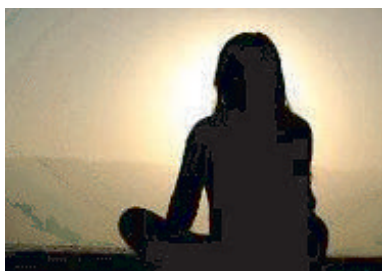

अब रोटी निकालने का चलन धीरे-धीरे कम हो गया है। ऐसे में गलियों-मोहल्लों में बाहर रहने वाले कुत्ते अपनी भूख मिटाने के लिए पहले खाना खोजते हैं और फिर असफल होने पर अपने भीतर होने वाले बदलावों के बाद कभी-कभार बच्चों या बड़ों पर हमला कर देते हैं। अधिकांश जीव आमतौर पर भूख और असुरक्षा के चलते ही किसी पर हमला करते हैं। ऐसे में उन्हें उस जगह से बलपूर्वक हटा देना उचित नहीं है। उनके लिए विकल्पों की तलाश नहीं के बराबर हो पाती है 1 जब उनके द्वारा कुछ अप्रत्याशित घटित होता है, तभी हमारा ध्यान उस ओर जाता है। सामान्य तौर पर कोई पशु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर उनकी जरूरत पूरी हो जाए या फिर वह अपने ऊपर कोई खतरा न महसूस करे।

कहा जाता है कि दुनिया की पहली मिठाई शहद है, जो हमें मधुमक्खियों से मिलता है। शहद की यह ताकत है कि वह स्वास्थ्यप्रद और औषधीय होने के साथ-साथ कभी खराब न होने वाला द्रव है। कितनी ही चिड़िया के फल खाने से बीज उनके पेट में चले जाते हैं और बीट के रूप में बाहर निकलते हैं। ये बीज चिड़ियों के पेट में रहने से उपचारित हो जाते हैं और उनके उगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पशुओं के खाने के बाद उनके शरीर से निकलने वाले बीज नए पेड़ बन कर जन्म लेते हैं। कितनी ही बार गिलहरियां बीज जमीन में अपने खाने के लिए छिपा देती हैं और फिर भूल जाती हैं, जिनके अंकुरण से पेड़ बन जाते हैं। तितलियों के फूलों पर बैठने से फूलों के परागकण उनकी टांगों में चिपक जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया सहज रूप से हो पाती है। कुत्तों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से सेना और पुलिस में कुत्तों को प्रशिक्षित करके अपराधी तक पहुंचा जाता है। घरों में कुत्ते घर की सुरक्षा करते हैं। मगर शहरी जानवर, पेड-पौधों और अपने आसपास की पारिस्थितिकी को जानते-बूझते, अकारण नुकसान पहुंचाना एक तरह की हिंसा ही है।

जल, वायु और मृदा- ये तीनों ही पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। हम अपने जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें इनका संरक्षण करना होगा, तभी इनसे संबंधित संसाधन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे और हम अपना जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे। अगर वन और वन्यजीव नहीं होंगे, तब जल, वायु और मृदा से मिलने वाले संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हम इनके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते।

जिस तरह से भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं, उसी तरह से बहुत से जीव भी कम या विलुप्त होते जा रहे हैं। शहरों में अब मोर और तोते कम दिखते हैं। लगभग पैंतीस-चालीस वर्ष पहले गिद्ध और चील आमतौर पर हर जगह दिखाई देते थे, जो अब नहीं के बराबर दिखते हैं। शहरों में तितलियां कम होती जा रही हैं। एक रपट के मुताबिक, फोन के टावर लगते रहने से मधुमक्खियां अपना रास्ता भूलने लगती हैं। बारिश के दिनों में निकलने वाली बीर- बहूटी कम होती जा रही है। लगातार पहाड़ों और जंगलों का कटना, नदियों और तालाबों का सूखना और शहरों के विस्तार कई जीवों के जीवन को संकट में डाला है। हम सब प्रकृति के हिस्से हैं। पारिस्थितिकी के मुताबिक अगर इस श्रृंखला की एक भी कड़ी टूटती है, तो उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इससे मानव जीवन भी अछूता नहीं रह सकता।

रीसाइक्लिंग हमारे प्लास्टिक संकट को हल नहीं कर सकती

डॉ विजय गर्ग

मूल तर्क यह है कि प्लास्टिक रीसाइक्लिंग मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट के पैमाने को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त है। अत्यधिक कम पुनर्चक्रण दरः लेख में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6% से भी कम प्लास्टिक अपशिष्ट का वास्तव में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। यह कम दर एक कठिन सत्य है जो जनता की समाधान के बारे में धारणा को चुनौती देती है। **प्लास्टिक को पुनर्चक्रित न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है: कांच और एल्युमीनियम जैसी सामग्रियों के विपरीत, प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बना होता है और इसमें लगभग 16,000 रसायन होते हैं जो छंटाई और पुनःप्रसंस्करण को कठिन बनाते हैं। प्लास्टिक की कार्यक्षमता कम हो जाती है: हर बार पुनर्चक्रित होने पर प्लास्टिक की गुणवत्ता में गिरावट आती है (एक प्रक्रिया जिसे ₹डाउनसाइक्लिंग₹ कहा जाता है)। एक प्लास्टिक की बोतल को केवल दो या तीन बार ही दूसरी बोतल में पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इससे पहले कि वह कालीन या कपड़े जैसा निम्न-स्तरीय उत्पाद बन जाए, जो अंततः लैंडफिल या भस्मक संयंत्र

में पहुंच जाएगा। विलंब करता है, प्रदूषण को नहीं रोकताः इस संदर्भ में पुनर्चक्रण से प्लास्टिक अपशिष्ट को पर्यावरण में समाप्त होने से स्थायी रूप से नहीं रोका जा सकता; यह केवल अपरिहार्य प्रदूषण में देरी करता है। जिम्मेदारी का मिथकः व्यक्तिगत रीसाइक्लिंग पर ध्यान केंद्रित करने को एक विकर्षण के रूप में देखा जाता है, या उपभोक्ताओं के लिए ₹अपने अपराध बोध को कम करनेर का एक तरीका माना जाता है, जबकि वास्तविक समस्या प्लास्टिक उद्योग द्वारा उत्पादन की भारी मात्रा है। 📈 प्लास्टिक की सच्ची कीमत लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि समस्या सिर्फ जीवन के अंत में होने वाले कचरे की नहीं, बल्कि प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र की है। व्यापक संदूषणः प्लास्टिक प्रदूषण विश्व के हर कोने तक पहुंच गया है, जिसमें आर्कटिक बर्फ, मारियाना ट्रेंच, दूरदराज के पहाड़ शामिल हैं, और चिंताजनक बात यह है कि यह पूरे मानव शरीर में पाया जा रहा है (माइक्रोप्लास्टिक के रूप में)। स्वास्थ्य और वित्तीय नुकसानः ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक में मौजूद रसायन कैंसर, दिल का दौरा पड़ना और हार्मोन संबंधी व्यवधान जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े होते हैं। प्लास्टिक से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी क्षति के लिए विश्व भर में प्रति वर्ष कम से कम 1.5 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है। 🎯 वास्तविक समाधान लेख का निष्कर्ष है कि चूंकि नुकसान उत्पाद की अवधारणा से शुरू होता है, इसलिए समाधान को स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिएः इतना अधिक प्लास्टिक का उत्पादन बंद करेंः प्राथमिक समाधान प्लास्टिक उत्पादन में भारी कमी होना चाहिए। पुनः प्रयोज्य और पुनःभरण योग्य प्रणाली में बदलाव, पुनर्चक्रण हमारे प्लास्टिक संकटों को हल नहीं कर सकता है: कंपनियों को अपने उत्पाद वितरण मॉडल को मौलिक रूप से फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है ताकि वे एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के बजाय कंटेनरों का पुनः उपयोग और पुनः भराव करने वाली प्रणालियों पर भरोसा करें। कानूनी कार्रवाईः लेख में कहा गया है कि राज्य के अटॉर्नी जनरल प्रमुख प्लास्टिक उत्पादकों (जैसे पेप्सीको और एक्सॉनमोबिल) के खिलाफ उनके प्रदूषण और भ्रामक पुनर्चक्रण दावे दोनों के लिए मुकदमा दायर कर रहे हैं।

रिटायर्ड प्रिंसिपल एजुकेशनल स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद

2026 में कक्षा 12 के बाद प्रवेश परीक्षाएं : डॉ विजय गर्ग

अचानक, आप आगे के कई विकल्पों से अभिभूत हो जाते हैं - इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कला, वाणिज्य, शीर्ष विश्वविद्यालय और पेशेवर पाठ्यक्रम।

सर्वोत्तम कॉलेजों में सीमित सीटों के लिए बड़ी संख्या में आवेदक उपस्थित होने के कारण, अधिकांश छात्रों के लिए इसका उत्तर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में निहित है।

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2026

जेईई मुख्य 2026 (संयुक्त प्रवेश परीक्षा)

भारत भर के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों का प्रवेश द्वार, जेईई मेन दो सत्र आयोजित करता है।

सत्र 1 जनवरी 21-30, 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि सत्र 2 अप्रैल 1 से 10, 1926 के लिए निर्धारित है।

सत्र 1 के लिए पंजीकरण अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुआ, जिसकी अंतिम तिथि 27 नवंबर, 2039 है।

यह परीक्षा कंप्यूटर-आधारित है, जिसमें गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू (बहुविकल्पीय प्रश्न) और संख्यात्मक प्रश्नों का मिश्रण होगा।

कठिनाई का स्तर मध्यम से उच्च है, जिसके लिए न्यूनतम 12 से 15 महीने की केंद्रित तैयारी की आवश्यकता होती है।

परीक्षा की अवधि प्रति पेपर तीन घंटे है।

जेईई एडवांस्ड

आईआईटी-जेईई मेन के बाद, यह प्रतिष्ठित परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश निर्धारित करती है।

अधिसूचनाएं मई 2026 में जारी की जाएंगी, और परीक्षाएं जून 2019 के लिए निर्धारित हैं।

परीक्षा पैटर्न में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित शामिल हैं, प्रत्येक पेपर तीन घंटे तक चलता है।

उम्मीदवारों को पात्र होने के लिए जेईई मेन के शीर्ष 2.5 लाख छात्रों में से एक होना चाहिए।

बिट्सैट 2026 (बिर्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट)

बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रवेश परीक्षा मई और जून 2026 में दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा।

पंजीकरण जनवरी में शुरू होता है और अप्रैल 2026 के मध्य तक बंद हो जाता है।

यह कंप्यूटर-आधारित परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी दक्षता और तार्किक तर्क का परीक्षण करती है।

अवधि 130 प्रश्नों के लिए तीन घंटे है।

कठिनाई का स्तर मध्यम है, जिसके लिए केवल याद करने के बजाय विषय में लगातार निपुणता की आवश्यकता होती है।

विटीईई 2026 (वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा)

वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी प्रवेश परीक्षा कई चरणों में आयोजित करेगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुई। परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 है।

परीक्षण में 130 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी समझ को शामिल किया गया है।

यह परीक्षा 2.5 घंटे तक चलेगी और उद्योग प्रथाओं के नियमित संपर्क के साथ गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा चाहने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है।

कोमेडक यूजीईटी 2026 (कर्नाटक के मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों का कंसोर्टियम-अंडरग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा)

कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए, कोमेडक यूजीईटी के लिए अधिसूचना फरवरी 2026 में जारी की जाएगी; परीक्षा मई 2019 में आयोजित की जाएगी।

पंजीकरण विंडो फरवरी और मार्च 2026 के बीच खुली रहेगी।

इस परीक्षा में 180 एमसीक्यू (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित से प्रत्येक 60) शामिल हैं और यह तीन घंटे में आयोजित की जाएगी।

कठिनाई का स्तर मध्यम है; फोकस अवधारणा स्पष्टता पर है।

राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा

जिन छात्रों ने कक्षा 12 में भाग लिया है/समाप्त किया है, उनके लिए विभिन्न राज्य-स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं हैं जैसे एपी ईएमसीईटी (आंध्र प्रदेश), टीएस ईएएमसीई (तेलंगाना), केसीएटी (कर्नाटक), एमएचटी-सीईडी (महाराष्ट्र), गुजेसेट (गुजरात), डब्ल्यूबीजीई (पश्चिम बंगाल), कीम (केरल), सीजी पीईटी [छत्तीसगढ़], असम सीईईईई (असम), जेजेईईई ट्रिपुरा), एचपीसी (चेतीमाचल प्रदेश), और अन्य।

इनमें से अधिकांश परीक्षाओं के लिए अधिसूचनाएं जनवरी और फरवरी 2026 के बीच जारी की जाएंगी; परीक्षाएं अप्रैल और मई 2019 के बीच आयोजित की जाएंगी।

राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित शामिल हैं।

कठिनाई बोर्ड-स्तर से लेकर मध्यम स्तर तक होगी।

कॉलेजों में प्रवेश केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से होगा।

अपने इंजीनियरिंग करियर की तैयारी करते समय, ध्यान रखें कि कई राज्य अब अलग-अलग सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के बजाय जेईई मेन और राज्य परामर्श परिणामों को प्राथमिकता देते हैं।

इन परीक्षाओं की अवधि - जो मुख्य रूप से आपको बोर्ड-संरेखित सामग्री पर परीक्षण करेंगी - तीन घंटे होगी, जिसमें MCQ प्रारूप में प्रश्न होंगे।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026

नीट यूजी 2026 (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा - स्नातक)

मेडिसिन के स्नातक और सर्जरी के स्नातक (एमबीबीएस), डेंटल सर्जरी के बैचलर (बीडीएस), आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी (बीएएमएस), यूनानी दवा और शल्य चिकित्सा (बीयूएमएस) के स्नातक और पूरे भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के स्नातक कार्यक्रम - नीट - का एकमात्र प्रवेश द्वार 3 मई, 2026 को (मई के पहले रविवार) आयोजित किया जाएगा, पंजीकरण फरवरी 2019 में खुलने और मार्च की शुरुआत में बंद होने के साथ।

पात्र होने के लिए आपको विज्ञान धारा में कक्षा 12 में होना होगा।

ऑफ़लाइन (पेन-एंड-पेपर) परीक्षा में 180 प्रश्न हैं (90 जीव विज्ञान, 45 भौतिकी, 46 रसायन विज्ञान) जिनका उत्तर तीन घंटे में दिया जाना है।

कठिनाई का स्तर मध्यम से उच्च है, तथा लगभग 15-16 लाख अभ्यर्थियों द्वारा सीमित संख्या के लिए प्रतिस्पर्धा करने के कारण उच्च प्रतिस्पर्धा होती है

यह विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में बीबीए, बीकॉम और एकीकृत एमबीए कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करता है।

यूजीएटी सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक कौशल, अंग्रेजी प्रवीणता और तार्किक तर्क का आकलन करता है।

यह परीक्षा वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें पंजीकरण आमतौर पर दिसंबर के अंत में शुरू होता है तथा परीक्षाएं वर्ष के मध्य में आयोजित होती हैं।

अन्य उल्लेखनीय यूजी प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं में एनएमआईएमएस-एनपीएटी (नरसी मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर ट्वेल्थ), आईपीमैट (इंटिग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट,) कुछ आईआईएम जैसे इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू और बोधगया और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के लिए डु जाट (दिल्ली विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षण) शामिल हैं।

कानून प्रवेश परीक्षा 2026

सीएलएटी 2026

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 24 राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में प्रवेश प्रदान करता है। परीक्षा के लिए अधिसूचना जुलाई 2026 में अपेक्षित है। आवेदन विंडो अक्टूबर 2026 में बंद हो जाएगी।

दो घंटे का सीएलएटी दिसंबर 2026 में ऑफ़लाइन मोड में आयोजित किया जाएगा; परीक्षा देने वालों को 120 एमसीक्यू का उत्तर देना होगा।

कठिनाई मध्यम है; परीक्षा आपको अंग्रेजी, कानूनी योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, तर्क और सामान्य ज्ञान में परखेगी।

ऐलेट 2026 (ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट)

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली इस परीक्षा को स्वतंत्र रूप से आयोजित करता है।

एआईएलईटी के लिए अधिसूचना जून 2026 में जारी की जाएगी।

इच्छुक और पात्र छात्र अगस्त से नवंबर 2026 के बीच आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा अस्थायी रूप से दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। परीक्षण प्रारूप CLAT के समान है तथा विषय पर थोड़ा अलग जोर दिया गया है।

परीक्षा की अवधि 90 मिनट है।

एसएलएटी (सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट)

एसएलएटी कई शहरों में सिम्बायोसिस लॉ स्कूलों में प्रवेश प्रदान करता है।

पंजीकरण आम तौर पर अगस्त-सितंबर 2026 से शुरू होता है, जबकि परीक्षा अक्टूबर 2019 में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की अवधि दो से तीन घंटे है।

150 एमसीक्यू होंगे।

कठिनाई मध्यम है, जिसमें कानूनी सोच और अंग्रेजी भाषा कौशल पर संतुलित जोर दिया गया है।

प्रबंधन प्रवेश परीक्षा 2026

ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (एआईएमए यूजीएटी) 2026

यह विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में बीबीए, बीकॉम और एकीकृत एमबीए कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करता है।

यूजीएटी सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक कौशल, अंग्रेजी प्रवीणता और तार्किक तर्क का आकलन करता है।

यह परीक्षा वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें पंजीकरण आमतौर पर दिसंबर के अंत में शुरू होता है और परीक्षाएं वर्ष के मध्य में होती हैं।

अन्य उल्लेखनीय यूजी प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हैं एनएमआईएमएस-एनपीएटी (बारहवीं के बाद कार्यक्रमों के लिए नर्सी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का राष्ट्रीय परीक्षण), आईपीएमएटी (प्रबंधन योग्यता परीक्षण में एकीकृत कार्यक्रम,) दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के लिए इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू और बोधगया जैसे कुछ आईआईएम में एकीकृत कार्यक्रमों के लिए।

सीयूईटी यूजी 2026

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित 200+ केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रदान करता है।

पत्थरों को प्राण देने वाले कलाकार का अंत: राम वनजी सुतार

25 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय तुलसी पूजन दिवस पर 551वृक्ष तुलसी वितरण एवं सामूहिक गौ भजन गौ आरती, तुलसी पूजा का भव्य कार्यक्रम भाग्यनगर गौशाला लोअर टैंकबैंट में संपन्न हुआ ...

25 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय तुलसी पूजन दिवस पर 551वृक्ष तुलसी वितरण एवं सामूहिक गौ भजन गौ आरती, तुलसी पूजा का भव्य कार्यक्रम भाग्यनगर गौशाला लोअर टैंकबैंट में संपन्न हुआ ...

देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान, श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट, सर्वदलीय गौरक्षा मंच, एवं उत्तराखंड महिला भजन मंडली आर के पूरम की ओर से दिनांक 25 दिसंबर 2025 को भाग्यनगर गौशाला लोअर टैंकबैंट में शाम 3.30 pm से 551 तुलसी के वृक्ष वितरण किए गए।

इस अवसर पर आज अनेक महापुरुषों का जन्म दिन भी मनाया गया। जिनमें प्रमुख रूप से कवि हृदय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेय, महाराज सूरज मल जी, योग गुरु बाबा राम देव जी, पंडित मदन मोहन मालवी जी, महाराज विजय पासी जी, पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और चक्रवर्ती राज गोपाला चार्य जी की पुण्य तिथि पर सभी महापुरुषों को याद किया गया।

इस अवसर पर अन्य समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने तुलसी पूजन और गौ पूजन मंत्रोचारण द्वारा देव दर्शन करवाएं।।

संत श्री गुलारामजी महाराज का भव्य जागरण सम्पन्न :

संत श्री गुलारामजी महाराज का भव्य जागरण सम्पन्न :

हैदराबादः बालाजीनगर स्थित श्री आईमाताजी वडेर में श्री श्री 1008 संत श्री गुलारामजी महाराज सेवा संघ भक्तों एवं समाज बन्धुओं के तत्वावधान में एक शाम संत श्री गुलारामजी महाराज के नाम जागरण गुरुवार दि. 25 दिसम्बर रात्रि 8.15 बजे भव्य रुप से आयोजित किया गया।

प्रेस द्वारा विज्ञप्ति में सेवा संघ के अध्यक्ष अचलाराम हाम्बड़, सचिव राजाराम सोयल ने संयुक्तरुप से बताया कि हर वर्ष की भांति रात्रि 8.15 बजे संत श्री गुलारामजी महाराज की भव्य जागरण का आयोजन किया गया। जिसमे राजयोगी राजगुरु चेतननाथ चौहान, जितू प्रजापत, भँवर सीरवी एवं मरुधरा की स्वर कोकिला अनिता जांगिड़ ने राजस्थानी अंदाज़ मे गुरुवर के चरणों में भजनों के पुष्प अर्पित किये। जिसका भक्तों ने देर रात तक नाचते-गाते हुए लाभ लिया। गायको ने कथा के माध्यम से गुला महाराज के गुणों का बखाण किया गया। भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर होकर देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम में पधारे विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस महोत्सव में हजारों की संख्या मे पधारे भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की गयी। जिसमें बडी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। सेवा संघ के अध्यक्ष अचलाराम हाम्बड़ ने भव्य जागरण मे पधारे समाज बन्धुओं का तहदिल से आभार प्रकट किया । मारवाड़ी युवा मंच मेड़चल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर मे भक्तो ने 53 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन मे सेवा संघ के अध्यक्ष अचलाराम हाम्बड़, सचिव राजाराम सोयल, कोषाध्यक्ष भंवरलाल हाम्बड़, संस्थापक केसाराम गेहलोत, ओमप्रकाश सोयल, समस्त कार्यकारणी सदस्य ।बालाजी नगर सीरवी समाज बडेर अध्यक्ष जयराम पँवार, उपाध्यक्ष नारायणलाल बर्फा, सचिव हीरालाल सोयल, सह सचिव डुगाराम सोलंकी , कोषाध्यक्ष नरेश सोलंकी ,सह कोषाध्यक्ष सोहनलाल , घेवराराम समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ताओं, महिला मंडल व समाज बन्धुओं का विशेष सहयोग रहा। मंच का संचालन पूनाराम सीरवी जोजावर ने अपनी ओजस्वी वाणी से किया । युट्युब लाईव एवं आईजी साउंड की व्यवस्था पी.एम.एल.सीरवी द्वारा की गयी। कार्यक्रम का विशेष कवरेज पत्रकार जगदीश सीरवी ने किया । महाआरती एवं सचिव राजाराम सोयल के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम का समापन हुआ ।

स्व श्रीमती सनु देवी सांखला की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 57 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ, रक्तदान शिविर को सफल बनाने में उनके भाई दिनेश, अनिल, सुमेर, के साथ साथ मारवाड़ी युवा मंच के सुशील भायल, गौतम भायल, दिनेश गौस्वामी का विशेष सहयोग रहा

मैसूरु में 28 दिसंबर को सीरवी महासभा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन, 3600 खिलाड़ी लेंगे भाग

बेंगलूरू: अखिल भारतीय सीरवी समाज के तत्वावधान में तथा आयोजक सीरवी स्पोर्ट्स क्लब एवं चेरिटेबल ट्रस्ट, मैसूर के संयुक्त तत्वावधान में सीरवी महासभा खेल प्रतियोगिता 2025–2026 का भव्य आयोजन दिनांक 28-12-2025 (रविवार) को मैसूर के जेके खेल मैदान में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भारत देश भर से विभिन्न राज्यों की टीमें भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता की तैयारियों के क्रम में सीरवी समाज मैसूर संस्था के अध्यक्ष ओगड़राम हाम्बड, ढगलाराम चोयल एवं अब्बाराम सीरवी ने सीरवी सेवा संघ लिंगराजपुरम वडेर के पदाधिकारियों को महाकुंभ महोत्सव की पत्रिका भेंट की। अब्बाराम सानपुरा ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में सीरवी समाज के करीब 3600 खिलाड़ी अलग-अलग खेलो में भाग लेगे। इसमें ओलंपिक के सभी खेल शामिल है। इस अवसर पर लिंगराजपुरम संस्था के सचिव अब्बाराम सानपुरा, नेमाराम गहलोत, तुलसाराम राठौड़, सीरवी महासभा कर्नाटक के महासचिव अमरचन्द सानपुरा सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता खेल भावना, अनुशासन एवं आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। देशभर से आने वाली टीमों की सहभागिता से आयोजन को राष्ट्रीय स्वरूप मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान होगा। आयोजकों ने समाजजनों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

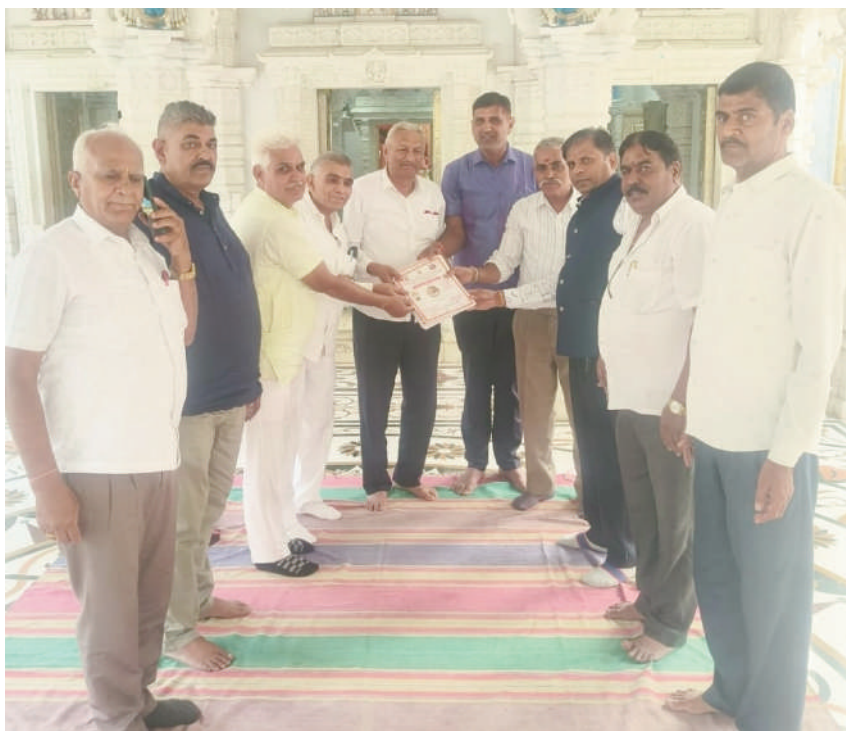

अन्तरराज्य अवैध हथियार कारोबार में जमशेदपुर के चार युवक बिहार मे धराये

ऐ के -47 कारतूस , देशी पिस्टल मैगजीन समेत नगदी बरामद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। बिहार के नालंदा में पुलिस और एसटीएफ अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान जमशेदपुर के चार युवकों को हथियारों के जखीरे और एके-47 के कारतूसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. लहेरी थाना क्षेत्र में हुई इस छापेमारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि यह गिरोह बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई चेन चला रहा था. पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है.

जांच में यह बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि आरोपियों ने बिहारशरीफ के सोहन कुआं मोहल्ले में एक फ्लैट किराये पर ले रखा था. इस फ्लैट का इस्तेमाल हथियारों की खरीद-बिक्री और डिलीवरी के लिए एक गुप्त ठिकाने यानी सेफ हाउस के रूप में किया जा रहा था.

गिरोह का सदस्य सौरभ झा, जो मूल रूप से मुंगेर का रहने वाला है,इस पूरे खेल में अहम कड़ी साबित हुआ है। उसने ही स्थानीय अपराधियों और जमशेदपुर से आने वाले तस्करों के बीच संपर्क सूत्र का काम किया ताकि हथियारों की डिलीवरी को सुरक्षित अंजाम दिया जा सके. सभी गिरफ्तार बदमाशों के पास से एके-47 राइफल के 153 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई कर रही है.

इस पूरे मामले में लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड से हथियारों का एक बड़ा सौदा बिहार में होने वाला है. इस जानकारी के बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया. जहां लहेरी थाना क्षेत्र के सोहनकुंआ गांव में एक किराए के मकान में दबिश दी गई. यहां बदमाशों द्वारा हथियारों की डील चल रही थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की छापेमारी में मौके से 5 देसी पिस्टल, 11 मैगजीन, 153 राउंड एके-47 कारतूस, 9 मोबाइल फोन, 24000 रुपये नकद और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है. ये हथियार और गोला-बारूद अपराधियों तक पहुंचने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए. पुलिस सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार शरीफ के गौरागढ़ मोहल्ला निवासी परवेज आलम, लहेरी के सोहनकुंआ में किराए पर रहने वाले सौरभ कुमार झा और झारखंड के जमशेदपुर निवासी 3 भाइयों जियार जई, मोहम्मद महबूब उर्फ टिंकू तथा जाहिद हुसैन के रूप में की है. पुलिस जांच में सामने आया है कि सौरभ कुमार झा भी मूल रूप से जमशेदपुर के ही रहने वाला है. परवेज आलम और सौरभ झा ने हथियारों की खरीद-बिक्री के लिए जमशेदपुर के आजाद नगर स्थित इन तीनों भाइयों को बिहार बुलाया था ।

विधायकों की सैलरी को लेकर रूलिंग पार्टी उलझन में: बीजेपी विधायकों का यू-टर्न

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वरः विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार उलझन में है। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में एकमत से बिल पास कर दिया। लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप सैलरी और अलाउंस में तीन गुना बढ़ोतरी को आसानी से स्वीकार नहीं कर रही है। इससे यह धारणा बन रही है कि पार्टी और सरकार की इमेज खराब हो रही है।आखिरकार, BJP ने इस मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है।जिन MLA ने 10 दिन पहले विधानसभा में सैलरी बढ़ाने का बिल पेश किया था, उन्होंने आज पार्टी ऑफिस में मुख्यमंत्री को फैसले पर दोबारा सोचने के लिए चिट्ठी लिखी। इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, इस पर सबकी नज़र है।

9 तारीख को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मुकेश महालिंग ने MLA, मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सरकार के चीफ एडवाइजर और डिप्टी चीफ एडवाइजर की सैलरी, अलाउंस और पेंशन बढ़ाने के लिए विधानसभा में तीन बिल पेश किए। उन्होंने दलील दी कि MLA की सैलरी आखिरी बार 2017 में रिवाइज की गई थी। इस दौरान, संसद के मेंबर और दूसरे राज्यों के MLA की सैलरी कई बार रिवाइज और बढ़ाई गई है। MLA और पूर्व MLA कई बार सैलरी और पेंशन बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए सैलरी बढ़ाई गई है। इस बदले हुए नियम से अब MLA और दूसरे लोगों की सैलरी हर पांच साल में एक बार बढ़ाई जाएगी। तीनों पार्टियों के MLA सरकार के इस बिल पर खुशी-खुशी सहमत हो गए। तीनों पार्टियों का किसी मुद्दे पर एक साथ होना एक रेयर एक्सेप्शन था।

कांग्रेसः सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई पूरी तरह से गैर-कानूनी: कांग्रेस

इसलिए सैलरी और पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी की अलग-अलग तरफ से कड़ी आलोचना हुई। कई जागरूक नागरिकों ने तर्क दिया कि ओडिशा जैसे पिछड़े राज्य में जनप्रतिनिधियों की सैलरी और अलाउंस में अचानक बढ़ोतरी सही नहीं थी। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन BJP के विधायकों ने मीडिया में इस सैलरी बढ़ोतरी के पक्ष में तर्क दिया। सत्ताधारी पार्टी के सीनियर विधायकों ने मीडिया में लगातार इस फैसले के पक्ष में बात की। यह जानने के बाद, BJP की सेंट्रल लीडरशिप ने राज्य लीडरशिप और सरकार से नाराजगी जताई। जबकि सांसदों की सैलरी अभी 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हुई है, BJP शासित राज्यों में विधायकों की सैलरी इससे बहुत ज़्यादा होना टॉप लेवल पर मंज़ूर नहीं था। मुख्यमंत्री के हाल ही में नई दिल्ली दौरे के दौरान, टॉप लीडरशिप ने उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की और अपनी नाराजगी जताई। राज्य लीडरशिप को बताया गया कि इससे गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए, किसी तरह से फैसले में बदलाव की रिक्वेस्ट की गई।

MLA की सैलरी और अलाउंस में बढ़ोतरी पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। BJD ने मुख्यमंत्री से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। विपक्षी पार्टी, जिसने विधानसभा में बिल का समर्थन किया था, जनता की नाराज़गी को देखते हुए फिर से विचार करने की मांग कर रही है, ऐसा विपक्षी पार्टी की नेता प्रमिला मलिक और उप नेता प्रताप देब ने कहा।

भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर चेतावनी दी, कहा—हिंसा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

संगिनी घोष विशेष संवाददाता परिवहन विशेष हिन्दी

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रही हिंसा पर कड़ा बयान दिया। मंत्रालय ने कहा कि इन घटनाओं को "मीडिया की बढ़ा-चढ़ाकर की गई खबरें" या केवल राजनीतिक हिंसा कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भारत ने साफ कहा कि ऐसे हमले गंभीर हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

MEA ने बताया कि भारत बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए है और अपनी चिंताएं वहां की सरकार के सामने रख चुका है। मंत्रालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बार-बार हो रहे ऐसे हमले एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं।

हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के दौरान हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन खबरों से भारत समेत कई देशों में चिंता बढ़ी है। भारत ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश की सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों की सुरक्षा करेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखेगी।

भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से अच्छे और दोस्ताना संबंध रहे हैं और भारत ने हमेशा वहां शांति और स्थिरता का समर्थन किया है। लेकिन भारत ने यह भी कहा कि अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी रही तो इसका असर आपसी रिश्तों पर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस मुद्दे को उठाता रहेगा और जल्द हालात सुधरने की उम्मीद करता है, ताकि वहां फिर से शांति और भाईचारा कायम हो सके।

चंद्रशेखर की सदस्यता रद्द कराने के लिए चत्तर सिंह रछौया ने खोला मोर्चा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दलित समाज के अधिकारों, संघर्षों और नेतृत्व की दिशा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। अखिल भारतीय रैगर महासभा (पंजी.) के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव चत्तर सिंह रछौया (चमार) ने लोकसभा अध्यक्ष के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए दलित राजनीति और वर्तमान नेतृत्व की भूमिका पर तीखे सवाल खड़े किए हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि दलित आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष या चेहरे तक सीमित नहीं हो सकता। यह आंदोलन डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों, मान्यवर कांशीराम के संगठनात्मक संघर्ष और सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई का परिणाम है। ऐसे में नेतृत्व की हर भूमिका का मूल्यांकन उसके भाषणों से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों और ज़मीनी काम से किया जाना चाहिए।

उम्मीदों पर खरा न उतरने का आरोप

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दलित समाज ने चंद्रशेखर सांसद को एक युवा, संघर्षशील और नई राजनीति के प्रतीक के रूप में देखा था। लेकिन आज समाज के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह नेतृत्व वास्तव में दलित समाज की पीड़ा, संघर्ष और वास्तविक मुद्दों के साथ खड़ा दिखाई देता है?

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, शिक्षा का संकट, महिलाओं की असुरक्षा और सामाजिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर ठोस हस्तक्षेप न होने को लेकर नाराज़गी व्यक्त की गई है। ज्ञापन के अनुसार, दलित आंदोलन की जमीन से जुड़ी समस्याओं पर नेतृत्व की स्पष्ट दिशा और सक्रियता दिखाई नहीं देती।

आंदोलन बनाम व्यक्ति

चत्तर सिंह रछौया ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ निजी हमला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रवृत्ति के विरुद्ध चेतावनी है। उन्होंने कहा कि दलित भावनाओं का उपयोग केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि आंदोलन कमजोर पड़ता है, तो कोई भी नेता इतिहास में टिक नहीं पाएगा।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जब नेतृत्व पर सवाल उठते हैं, तो चुप्पी लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। जनता जवाब चाहती है—नेतृत्व किस विचारधारा के साथ खड़ा है और दलित आंदोलन को किस दिशा में ले जाया जा रहा है।

अंबेडकर–कांशीराम के मार्ग पर लौटने की अपील

ज्ञापन के अंत में बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के विचारों को दोहराते हुए कहा गया है—

"शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो।"

लेखक के अनुसार, यही मार्ग दलित समाज के उत्थान, बहुजन राजनीति के पुनर्निर्माण और नेतृत्व की जवाबदेही तय करने का एकमात्र रास्ता है।

दलित आंदोलन किसी नाम का मोहताज नहीं, बल्कि सिद्धांतों और संघर्षों का परिणाम है—यह संदेश इस ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रूप से सामने आया है।

मोबिल ऑयल ने कानपुर में एक दर्जन राहगीरों को पहुंचाया अस्पताल : तीन गम्भीर

सुनील बाजपेई

कानपुर। आज यहां शुक्रवार की सुबह किसी अज्ञात वाहन से नेशनल हाईवे पर फैलाए गये मोबिल ऑयल ने एक दर्जन को अस्पताल पहुंचा दिया। आज सुबह यह घटना सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भौती नेशनल हाईवे पर हुई, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। फिर भी रफ्तार में सड़क पर फैले हुए मोबाइल मिल की वजह सेलगभग एक दर्जन राज वीरों को अस्पताल पहुंचा दिया जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस के मुताबिक किया घटना अज्ञात वाहन से बीच हाईवे पर मोबिल ऑयल गिर जाने के कारण हुई जिसके फल स्वरुप देखते ही देखते बाइक सवारों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की कई बार सूचना दी गई, लेकिन शुरुआती समय में पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे घायलों की संख्या बढ़ती गई। एक किमी तक फैला तेल, लगा भीषण जाम अज्ञात वाहन से गिरा तेल लगभग एक किलोमीटर के दायरे में फैल गया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। बाद मे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालते हुए फिसलन कम करने के लिए सड़क पर भूसी और मिट्टी डलवाई है।

विधायक डॉ. निज्जर और मेयर भाटिया ने नई निर्माण योजना के तहत 114 लाभार्थियों को 2.85 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए

अमृतसर, 26 दिसंबर (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी की मान सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करते हुए आज अमृतसर दक्षिणी से विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर एवं नगर निगम अमृतसर के मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत नई निर्माण योजना के तहत 114 लाभार्थियों को कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपये के चेक वितरित किए।

इस अवसर पर विधायक डॉ. निज्जर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से क्षेत्र में सरकार की आवासीय योजनाओं को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा था। जरूरतमंद परिवारों से सरकारी हिस्सेदारी के लिए आवेदन भरवाए गए तथा नगर निगम की टीम के निरंतर फॉलो-अप के परिणामस्वरूप आज यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता गरीब परिवारों के लिए अपने सपनों का घर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने कहा कि मान सरकार ने इस योजना में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जहां पिछली सरकारों के समय पंजाब सरकार की ओर से केवल 25 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, वहीं मान सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इससे हजारों गरीब परिवारों के लिए नया मकान बनाना अब और अधिक आसान व सुलभ हो गया है।

उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य जन-हितैषी नीतियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाना मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

अंत में विधायक डॉ. निज्जर ने कहा कि मान सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देना है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लंबित मामलों को भी शीघ्र निपटाकर अन्य लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर विधायक डॉ. निज्जर और मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

डाक सेवा जन सेवा में अमृतसर डाक मंडल द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं बेहतर सेवाएं

अमृतसर 26 दिसंबर (साहिल बेरी)

आम लोगों के आधार कार्ड में सुधार का काम जल्द से जल्द हो, आधार बनवाने में भाग दौड़ या लम्बी कतार में नही लगना पड़े, इसके लिए अमृतसर डाक मंडल के सभी डाकघरों में आधार काउंटर एक्टिव करने का कार्य किया जा रहा है। अभी वर्तमान में प्रधान डाक घर अमृतसर में दो काउंटर कार्य कर रहे हैं साथ ही अमृतसर जिला के अंतर्गत उपडाकघर गांधी बाजार, छेहरटा, गोल्डन टेंपल, गुरुनानकदेव यूनिवर्सिटी, रईया, अमृतसर कचहरी, खालसा कॉलेज, मजीठ मंडी, अजनाला में आधार के काउंटर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। डाक अधीक्षक (मुख्यालय) अमृतसर, श्री प्रवीण प्रसून ने इस संदर्भ में बताया कि जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े डाकघरों में 2-3 काउंटर खोले जाएंगे ताकि लोगों को आधार का कार्य करवाने में परेशानी न हो। पार्सल के लिए डाकघर में दी जा रही सुविधा के संदर्भ में बताया कि लोगों को देश विदेश में पार्सल भेजने में उनके समान को अच्छे ढंग से पैक करने के लिए सभी डाकघरों में पार्सल पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई जो कि काफी कम दरों पर की जाती है ताकि उनका समान सुरक्षित व समय से उनके संबंधी को मिल सके। प्रवर डाकपाल, अमृतसर श्री धीरज कुमार ने बताया कि अमृतसर प्रधान डाकघर में विदेश भेजने वाले आर्टिकल को बुक करने के लिए विशेष कॉन्टर की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को लंबी कतार में न लगना पड़े। बल्क बुकिंग करवाने वाले ग्राहकों को पिकअप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसे में उनकी डाक को उनके कार्यालय परिसर से ही डाक कर्मचारी द्वारा पिकअप कर के बुकिंग करवाकर रसीद उन्हें दे दी जाएगी। डाक विभाग ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा विशेष सुविधा देने के लिए प्रयासरत है।

जनवरी से शुरू होगी 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना', हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज : दलवीर सिंह टोंग

अमृतसर, 26 दिसंबर (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी के अमृतसर के हलका बाबा बकाला से विधायक दलवीर सिंह टोंग ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि पंजाबवासियों के लिए नए साल के विशेष तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जनवरी माह से 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा, जो पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

टोंग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस योजना की जानकारी बड़े स्तर पर आम जनता तक पहुंचाई जाए, ताकि हर पात्र परिवार को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को महंगे इलाज के बोझ से मुक्त करेगी और गरीब से गरीब परिवारों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। टोंग ने आगे कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला हर परिवार के लिए जीवनदान साबित होगा, क्योंकि इलाज की बढ़ती लागतों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी थी। अब लोग बिना किसी आर्थिक चिंता के सरकारी और निर्धारित निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। अंत में टोंग ने कहा कि मुख्मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे जन-कल्याणकारी कार्य यह सिद्ध करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल वादे ही नहीं करती, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना पंजाब के हर नागरिक को विश्वास और सुरक्षा प्रदान करेगी।

संत श्री गुलारामजी महाराज का भव्य जागरण सम्पन्न :

बोबा और विजयी उम्मीदवारों को दिल से बधाई दी।

बराड़ ने कहा कि यह जीत पार्टी की ईमानदार, जन-केंद्रित और विकासोन्मुख नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने हमेशा गांवों और ब्लॉक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सड़कों और रोज़गार जैसे मूल मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम आज जनता के समर्थन के रूप में सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि विजयी प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे और विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। यह जीत पंजाब में नई राजनीति और पारदर्शी प्रशासन की मज़बूत नींव साबित होगी। अंत में, बराड़ ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के अधिकारों और विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुलाता पंडा को मिला अटल नारीश्री अवॉर्ड

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: अटल बिहारी वाजपेई

जयंती बैठक ऑडिटोरियम में डॉ. बंसी धर दाश की अध्यक्षता में हुई। मुख्य वक्ता IAS कल्याण राय थे, गेस्ट ऑफ ऑनर पंडित प्रबोध मिश्रा, डॉ. लादुकिशोर पढियारी थे। अटल बिहारी वाजपेयी रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाता है और ओडिशा की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का सम्मान करता है। ओडिशा के लोगों के लिए खुशी का मौका। भुवनेश्वर में, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक संस्था 12 सालों से देशभक्ति, स्वाभिमान, निस्वार्थता और साहस फैला रही है। अब इस संस्था ABVRI ने गुड गवर्नेंस डे पर ओडिशा की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का सम्मान किया। ऐसे पॉपुलर टैलेंट को चुनकर अटल बिहारी वाजपेयी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। सुलता पांडा को नारीश्री अवॉर्ड, विनोद शसमल को पत्रकारिता, संजुक्ता रानी राउत को सुंदरगढ़ के आदिवासी इलाकों में हेल्थ सर्विस देने और प्रियंबदा परिदा को नर्सिंग सर्विस के लिए सम्मानित किया गया। पूरे ओडिशा से कई कामयाबियों और टैलेंट को सम्मानित किया गया।

जानकी बल्लव की जन्म शताब्दी 3 जनवरी को मनाई जाएगी, मोहन, नवीन समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : पूर्व मुख्यमंत्री और असम के पूर्व राज्यपाल जानकी बल्लव पटनायक की जन्म शताब्दी 3 जनवरी, 2026 को कैपिटल हाई स्कूल ग्राउंड में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल शिवाल, CPI के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व MP डी राजा, AICC के प्रवक्ता और राज्यसभा MP रणदीप सिंह सुरजेवाला इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जानकी बल्लभ पटनायक जन्म शताब्दी समिति के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

मुन्ना खान ने नवीन के सामने पांडियन पर निशान सादा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : BJD के स्थापना दिवस पर सांसद मुन्ना खान ने बिना नाम लिए पांडियन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम बीजू बाबू के रास्ते पर चल रहे थे। नवीन बाबू के आने के बाद चीजें थोड़ी बदलीं। बीजू बाबू कहते थे कि जो अधिकारी काम नहीं करते उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। लेकिन हमारे नेता नवीन ने हमें शांति और व्यवस्था का पाठ पढ़ाया मैंने नवीन से पहले ही कह दिया है कि अब हम बीजू बाबू का फॉर्मूला अपनाएंगे। हम इन दो मुंह वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अगर दो मुंह वाले लोग दोनों तरफ से चालाकी दिखाएंगे, तो यह अब काम नहीं करेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग ... 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023